सोमवार को बीरभूम जिले की बारशल ग्राम पंचायत टीएमसी के एक पंचायत नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 10 लोगों की मौत की खबर है। इन लोगों के घरों को आग लगा दी गई थी, जिसमें वे जिंदा जलकर मर गए।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्षः27 अंकः 98 दिनांकः 23-03-2022 बुधवार मूल्य : 100 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

पुष्कर सिंह धामी बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री शाह भाजपा अध्यक्ष नड्डा कई केंद्रीय मंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

प. बंगाल में फिर सियासी हिंसा पनपी, टीएमसी नेता की हत्या के बाद फूंके घर, 10 लोग जिंदा जले

कोलकाता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा का बर्बर दौर गुजरने के बाद एक बार फिर सियासी हिंसा दौर शुरू होता दिख रहा है। सोमवार को टीएमसी के एक पंचायत नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 10 लोगों की मौत की खबर है। इन लोगों के घरों को आग लगा दी गई थी, जिसमें वे जिंदा जलकर मर गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस ने कहा कि बीरभूम जिले की बारशल ग्राम पंचायत के उप-प्रधान भादू शेख की सोमवार को हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ही रात को यह आगजनी कांड हुआ, जिसमें 10 लोग जिंदा जल गए। भादू शेख बोगतुई गांव के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आगजनी टीएमसी के एक गुट के सदस्यों की ओर से की गई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। बीरभूम जिले के टीएमसी के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने मंगलवार दोपहर को दावा किया कि यह आग हिंसा के दौरान नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि यह आगजनी शॉर्ट सर्किट के चलते हुई थी और उसी की वजह से घरों में आग लग गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से हमले की बात को खारिज करते हुए मंडल ने कहा, 'शॉर्ट सर्किट के चलते लोगों के घरों में आग लग गई थी और उससे ही मौतें हुई हैं। सोमवार की रात को कोई हिंसा नहीं हुई थी।'

फायर ब्रिगेड के एक कर्मचारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि उन्होंने कम से कम 10 घरों को आग से बर्बाद पाया है। उन्होंने कहा, 'हमें कुछ स्थानीय लोगों ने आग बुझाने से भी रोका। अब तक हमें एक घर से 7 शव मिल चुके हैं। वह इतनी बुरी तरह से जले हैं कि यह भी नहीं पहचान हो पाई कि मरने वाले पुरुष थे, महिला थे या फिर नाबालिग हैं।' फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम और रामपुर हाट के विधायक आशीष बनर्जी मौके पर पहुंच रहे हैं।

टीएमसी के पंचायत लीडर भादू शेख पर मोटर साइकिल सवार 4 लोगों ने हमला किया था। हमलावरों के चेहरे ढंके हुए थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो सकी। गोलियां मारे जाने के तुरंत बाद शेख को रामपुर हाट के सरकारी अस्पातल में ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि यह घटना टीएमसी के ही दो गुटों के बीच जारी प्रतिद्वंद्विता के चलते हुई है। इसी के चलते बड़ी संख्या में घरों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया।

सोनिया ने 'जी23' के कुछ नेताओं के साथ बैठक की

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के मंगलवार को 'जी-23 समूह के कुछ अन्य नेताओं के साथ बैठक की। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा और लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने सोनिया गांधी के आवास '10 जनपथ पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस बीच, जानकारी सामने आई है, कि आजाद ने भी समूह के कुछ अन्य नेताओं से मुलाकात की है।

सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व जी-23 का पक्ष सुनकर मतभेदों को दूर कर तथा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए समाधान चाहता है। 'जी 23' समूह के प्रमुख सदस्य आजाद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर कहा था कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने सिर्फ संगठन को मजबूत बनाने तथा आगे के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। आजाद का यह बयान इस मायने में अहम था कि इससे कुछ दिनों पहले ही 'जी 23 के उनके साथी कपिल सिब्बल ने खुलकर कहा था कि गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य नेता को मौका देना चाहिए। 'जी 23' समूह पार्टी में संगठनात्मक बदलाव और सामूहिक नेतृत्व की मांग कर रहा है।

घरेलू सिलोंडर पर 50 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के खत्म होने के बाद जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, वह अंततः सही सिद्ध हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 2008 के बाद रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं। लेकिन इसके कारण कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमत रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन देश में उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमत में दिवाली से कोई बदलाव नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में भारी बढ़ोतरी के कारण तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था। आखिर आज महंगाई बम फूट गया। पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है जबकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

पेट्रोल और डीजल की कीमत में 137 दिनों के बाद बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद मंगलवार से दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपए से बढ़कर 96.21 रुपये हो गई है जबकि डीजल अब 86.67 रुपये के बजाय 87.47 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। इससे पहले दिवाली के दिन यानी चार नवंबर, 2021 को पेट्रोल और डीजल की कीमत में बदलाव हुआ था। तब केंद्र ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज डयूटी में कटौती की थी क्योंकि कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार चली गई थी।

आज की बढ़ोतरी के बाद मुंबई में डीजल 95.00 रुपये और पेट्रोल 110.82 रुपये पहुंच गया है। इसी तरह कोलकाता में डीजल 90.62 रुपये और पेट्रोल 105.51 रुपये लीटर हो गया है। चेन्नई में एक लीटर डीजल के लिए आपको 92.19 रुपये व पेट्रोल के लिए 102.16 रुपये चुकाने होंगे। लखनऊ में पेट्रोल 96.08 रुपये और डीजल 87.61 रुपये पहुंच गया है। पटना में पेट्रोल की कीमत 106।72 रुपये और डीजल की कीमत 91.90 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल के साथ आज घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है जो आज से लागू हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली और मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 949.50 रुपये हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 976 रुपये, चेन्नई में 965.50 रुपये और लखनऊ में 987.50 रुपये चुकाने होंगे। देश में घरेलू रसोई गैस के दामों में इससे पहले छह अक्टूबर 2021 को बढ़ोतरी की गई थी।

कश्मीरी पंडितों के नरसंहार मामले में आमने-सामने आए फारूक अब्दुल्ला और भाजपा

उमर अब्दुल्ला ने बोल झूठ

नई दिल्ली (ईएमएस)। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मामले पर भाजपा और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आमने सामने आ गए हैं। भाजपा के आरोपों पर पलटवार कर अब्दुल्ला ने कहा कि आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले का सच सामने लाने के लिए एक आयोग बनाकर जांच होनी चाहिए। उन पर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब देकर उन्होंने दोहराया कि जांच आयोग बनाया जाए जहां वहां अपना पक्ष रखने को तैयार हैं। हालांकि जिम्मेदारी को लेकर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर फारूक अब्दुल्ला भड़कते हुए भी नजर आए।

दरअसल, भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम के दस्तावेज को शेयर करते हुए ट्वीट कर यह आरोप लगाया था कि उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही कश्मीरी पंडितों का नरसंहार शुरू हो गया था। मालवीय ने ट्वीट कर लिखा ,उमर ने दावा किया कि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला नरसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं थे। यह झूठ था। यह फारूक अब्दुल्ला द्वारा पेश किया गया जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम है, जिसमें पलायन के लिए कट ऑफ की तारीख 1 नवंबर 1989 है। मालवीय ने इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधकर लिखा कि, 18 जनवरी 1990 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तक उन्होंने उन 79 दिनों तक क्या किया ?

तेल-गैस की बढ़ी कीमतों पर सियासी हमला लोकसभा राज्यसभा में भारी हंगामा

नई दिल्ली (ईएमएस)। पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के इस डबल अटैक से जहां एक तरफ लोगों को जेब ढीली करनी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ संसद के दोनों सदनों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों की तरफ से इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया गया। दूसरी तरफ, इसको लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से केन्द्र सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा-गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा 'लॉकडाउन' हटा दिया गया है। अब सरकार्रहेंज्; कीमतों का 'विकास' करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए, तो वे कहेंगेंहेंज्; थाली बजाओ लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद ईंधन की कीमतों में इजाफा होगा। हम बिल्कुल सही साबित हुए। मोदी सरकार गरीबों की लूट पर अमादा है। लेकिन हम लोकसभा के अंदर और बाहर इस रूख के खिलाफ आम जनता के साथ खड़े रहेंगे। इधर, राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर केन्द्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफा कर मोदी सरकार 10 हजार करोड़ रुपये बनाने जा रही है। कई लोग यह कहते हैं कि यूक्रेन-रूस संकट के चलते तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हम रूस से 1 फीसदी भी कच्चे तेल की खरीददारी नहीं करते हैं।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और विधानसभा चुनाव बीतने के बाद महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए मंगलवार की सुबह ट्वीट किया, ''जनता को दिया भाजपा सरकार ने महंगाई का एक और उपहार लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ हजार के पास और पटना में हजार के पार।'' इसी ट्वीट में अखिलेश ने लिखा, ''चुनाव खत्म, महंगाई शुरू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर, जबकि घरेलू रसोई गैस के दाम में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई। इस तरह, चुनावी गतिविधियों के कारण पेट्रोल, डीजल की दरों में संशोधन पर साढ़े चार महीने से जारी रोक खत्म हो गई।

सरकार ने लोकसभा में बताया, पीओके में अनेक लांच पैडों पर बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद

नई दिल्ली (ईएमएस)। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में अनेक लांच पैडों पर बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि सीमापार से घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2018 में इस तरह की 143 घटनाएं, 2019 में 138 घटनाएं और 2020 में 51 घटनाएं घटीं, वहीं 2021 में 34 इसतरह के मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान और भारत पिछले करीब एक साल से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम का पालन कर रहे हैं। क्या एलओसी पर पाकिस्तान ने बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और क्या आतंकवादियों ने सीमापार से लांच पैडों से घुसपैठ की कोशिश की है, इस बारे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, मांगी गई जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील अभियान संबंधी मामले से संबंधित है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इस बताया नहीं जा सकता।'' हालांकि राय ने कहा कि केंद्र सरकार एलओसी पर सुरक्षा हालात की नियमित समीक्षा कर आतंकवादियों समेत अन्य खतरे वाले तत्वों की किसी भी हरकत को नाकाम करने के लिए एहतियाती कदम उठाती है।

शशि थरूर के खिलाफ एकजुट हुई केरल कांग्रेस, कई सांसदों ने मिलकर सोनिया से की शिकायत

नई दिल्ली (ईएमएस)। केरल के कई कांग्रेस सांसदों ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से अलग से मुलाकात कर पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की शिकायत की। दरअसल, थरूर ने सीपीएम के 'पार्टी कांग्रेस' के तहत हो रही कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार किया है, जिसे लेकर राज्य कांग्रेस नेताओं में उनके प्रति रोष है।

बाद में सोनिया ने कहा कि वह इस मामले में पीसीसी की शिकायत पर विचार करेंगी। कांग्रेस की केरल इकाई के प्रमुख के सुधाकरण ने कहा कि पार्टी ने अपने नेताओं को कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर दिया है, क्योंकि वह प्रस्तावित के-रेल परियोजना को लेकर राज्य की माकपा नीत सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है।

बहरहाल, थरूर ने कहा कि जिस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है उसका विषय केरल या के-रेल से संबंधित नहीं है। थरूर ने कहा उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। इस बार उन्होंने मुझे अपनी 'पार्टी कांग्रेस' के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। राजनीतिक संवाद में शामिल होने में कुछ भी गलत नहीं है और संगोष्ठी का विषय के-रेल या केरल से संबंधित नहीं है। माकपा का आमंत्रण कांग्रेस नेता केवी थॉमस ने भी स्वीकार किया है।

थरूर और थॉमस दोनों कांग्रेस आलाकमान से संपर्क करने की योजना बना रहे हैं ताकि पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी से कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मांग सकें। वाम दल ने तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर और पूर्व केंद्रीय मंत्री थॉमस को कन्नूर में छह-10 अप्रैल तक होने वाले उसके 23वीं 'पार्टी कांग्रेस' से पहले विभिन्न संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

वहीं, माकपा के राज्य सचिव के बालकृष्णन ने कहा कि वाम दल ने विभिन्न संगोष्ठियों के लिए कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन उनकी पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें इनमें शिरकत करने से मना कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रजातांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) वाम सरकार की प्रस्तावित महत्वाकांक्षी 'अर्ध-हाईस्पीड सिल्वरलाइन' रेल परियोजना को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है।

यूपी में योगी कैबिनेट की कवायद, केशव मौर्य फिर बन सकते हैं डिप्टी सीएम

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा दोबारा सरकार करने जा रही है। मंत्रिमंडल की घोषणा होना अभी बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा उप-मुख्यमंत्री बना सकती है। साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह को भी कैबिनेट में अहम पद दिया जा सकता है। भाजपा ने योगी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है। एक रिपोर्ट में भाजपा के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि इस पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। वहीं, एक और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जगह कोई ब्राह्मण चेहरा, बृजेश पाठक या कोई और ले सकता है। खबर है कि 24 मार्च को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अहम पदों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी तीसरे उप-मुख्यमंत्री पद पर भी विचार कर रही है। इस पद के लिए आगरा ग्रामीण से विधायक बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी कैबिनेट तैयार करने पर विचार कर रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने से नए विकल्प तलाश रहे दलित वोट बैंक को भी भाजपा जीतने की कोशिश कर रही है। इसी तरह प्रदेश इकाई के प्रमुख सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने के फैसले को गैर-यादव ओबीसी वोट से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जाता है कि यह वर्ग साल 2014 से ही पार्टी का वफादार रहा है।

फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं - यूपीएससी ने सुको में कहा

नई दिल्ली (ईएमएस)। संघ लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है तो फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।शीर्ष अदालत तीन उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने यूपीएससी-2021 प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी लेकिन कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्य परीक्षा के सभी पेपरों में उपस्थित नहीं हो सके और अब परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

यूपीएससी ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में आयु में छूट और प्रतिपूरक / अतिरिक्त प्रयास के संबंध में कोई भी निर्णय एक ''नीतिगत मामला'' है जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दायरे में आता है।उसने कहा, ''आयोग आमतौर पर एक वर्ष के दौरान 13 परीक्षाओं के अलावा कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। इन परीक्षाओं के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी भी बीमारी/दुर्घटना सहित किसी भी कारण से निर्धारित तारीख पर परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है, जिससे वह परीक्षा देने में असमर्थ हो जाता है, तो फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।''

आयोग ने कहा, ''अतीत में, आयोग ने समान परिस्थितियों में कोई पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की है।'' हलफनामे में कहा गया है कि यूपीएससी भारत सरकार द्वारा कार्मिक मंत्रालय में सालाना बनाए गए परीक्षा के नियमों के अनुसार ही सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है।

पुष्कर सिंह धामी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, पीएम नरेन्द्र मोदी रहेंगे मौजूद

देहरादून। उत्तराखंड के पांचवें विधानसभा चुनाव में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने के बाद भाजपा के नेता विधायक दल चुने गए पुष्कर सिंह धामी बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। देहरादून के परेड मैदान में दोपहर ढाई बजे आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री धामी के अलावा मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सहित पूर्ण 12 सदस्यीय मंत्री परिषद शपथ ग्रहण करेगी। कुछ नए चेहरों को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। समारोह में संत समाज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। धामी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को मेगा इवेंट बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। शपथ ग्रहण को भव्य स्वरूप देने के साथ ही इसके माध्यम से यह संदेश देने का भी पार्टी प्रयास करेगी कि वह राज्य में विकास की रफ्तार को तेजी से बढ़ाने और जनाकांक्षाओं को पूरा करने के अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देगी।

उत्तराखंड से विशेष लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति समारोह को गरिमा प्रदान करेगी। उनके अलावा गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी समेत कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष सहित पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, उप्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या समेत अन्य अतिथि शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के अनुसार समारोह में साधु-संतों, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों, प्रबुद्धजनों, मातृशक्ति समेत हर वर्ग के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले बुधवार सुबह मंडल स्तर तक के सभी कार्यकत्ता मंदिरों में पूजा-अर्चना करेंगे तो गुरुद्वारों में अरदास होगी।

चर्चा है कि धामी मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों के नाम तय करने के मद्देनजर केंद्रीय नेतृत्व को सूची भेजी गई है। इसमें सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, बिशन सिंह चुफाल, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, बंशीधर भगत, गणेश जोशी, चंदनरामदास, खजानदास, सौरभ बहुगुणा, ऋतु खंडूड़ी, उमेश शर्मा काऊ, प्रदीप बत्रा, आदेश चौहान, प्रीतम पंवार आदि के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन के मामले में भारत के रुख पर चिंता जाहिर की

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर भारत के रुख पर चिंता जाहिर की है। बाइडेन का कहना है, कि यूक्रेन पर रुसी आक्रमण के खिलाफ समर्थन दिखाने में भारत की स्थिति थोड़ी असमंजस वाली है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ज्यादातर मित्रों और सहयोगियों ने व्लादिमीर पुतिन के 'आक्रामक रुख से निपटने में एकजुटता जाहिर की है। रूस की सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया जो अब तक जारी है। हमले से तीन दिन पहले रूस ने यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी।

बाइडन ने कहा, पुतिन को अच्छी तरह जानने के कारण एक चीज को लेकर मैं आश्वस्त हूं कि वह नाटो को विभाजित करने में सक्षम होने का भरोसा कर रहे थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि नाटो सुलझा हुआ रहेगा, पूरी तरह एकजुट रहेगा। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, कि नाटो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कारण आज के मुकाबले पहले कभी इतिहास में इतना मजबूत या अधिक एकजुट नहीं रहा।' उन्होंने कहा, ''उनके आक्रामक रुख के जवाब में नाटो और प्रशांत क्षेत्र में एकजुटता दिखाई है। भारत के अलावा क्वाड एकजुट है। भारत की स्थिति पुतिन के आक्रमण से निपटने के लिहाज से थोड़ी असमंजस वाली है, लेकिन जापान अत्यधिक मजबूत है, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी मजबूत दिख रहा हैं।

पिछले माह बाइडन ने कहा था कि भारत और अमेरिका, यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के मुद्दे पर अपने मतभेदों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बैठक में कहा, 'हमने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और प्रशांत क्षेत्र में एकजुटता दिखाई और आपने रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और प्रतिबंध लगाने में हमारी मदद के लिए काफी कुछ किया।

कार्टून कोना

ईडी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार की संपत्ति जब्त की

मुंबई (ईएमएस)। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय - ईडी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार की संपत्ति जब्त की है। इसके ईडी ने पुष्पक ग्रुप की कंपनियों में शामिल पुष्पक बुलियन की 6।45 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अटैच किया है। इस अटैच संपत्ति के तहत ठाणे के नीलांबरी प्रोजेक्ट के तहत 11 आवासीय फ्लैट को भी सीज किया गया है। यह प्रोजेक्ट श्री साईबाबा गृहानिरमिति प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। इनका स्वामित्व और नियंत्रण श्रीधर माधव पाटनकर के पास है।ईडी का यह कदम आयकर विभाग की हाल ही में उन सिलसिलेवार छापेमारी के बाद सामने आया है, जिसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ छापेमारी शामिल है। शिवसेना लगातार इसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और राजनीतिक तौर पर बदले की कार्रवाई बताती रही है।

मुख्यमंत्री के रिश्तेदार की संपत्ति जब्त करने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे तानाशाही और प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने पुष्पक बुलियन और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ 6 मार्च 2017 को मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था और अस्थायी तौर पर पुष्पक बुलियन की 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति को जब्त किया था। यह संपत्ति महेश पटेल, चंद्रकांत पटेल और उनके परिवार और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों की थी। बाद की जांच से पता चला कि महेश पटेल ने नंदकिशोर चतुर्वेदी (आवास सुविधा प्रदाता) की मिलीभगत से पुष्पक समूह की कंपनी मेसर्स पुष्पक रियल्टी के धन का गबन और हस्तांतरण किया था। पुष्पक रियल्टी डेवलपर ने बिक्री, फंड ट्रांसफर की आड़ में 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति नंदकिशोर चतुर्वेदी द्वारा नियंत्रित कंपनियों को दी। इसे अन्य कंपनियों के जरिये घुमाफिराकर उन तक पहुंचाई गई।

किसान नेता अनिल घनवत ने कहा कि विवादित कृषि कानूनों पर सभी से राय ली

नई दिल्ली (ईएमएस)। कृषि कानूनों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई तीन सदस्यीय समिति के एक सदस्य, किसान नेता अनिल घनवत ने इस आलोचना को सिरे से नकार दिया कि उन्होंने सिर्फ, विवादित कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसानों से ही राय ली। एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान घनवत ने बताया कि जिनकी राय ली गई, उन संगठनों के नाम उनके पास नहीं हैं लेकिन ऊध फाइल करके यह सूची प्राप्त की जा सकती है।

ज्ञात रहे कि सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुणे निवासी किसान नेता ने कहा था कि उन्होंने रिपोर्ट जारी किए जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट को तीन बार लिखा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्हें खुद यह करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित इस समिति के दो अन्य सदस्य-अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और कृषि अर्थशास्त्री प्रमोद कुमार जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिन किसानों से उन्होंने बात की, उसमें से 86ङ्म कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं थे। कमेटी की ओर से जिन 61 संगठनों से बात की गई, उनके नाम भी रिपोर्ट में नहीं हैं। घनवत ने कहा कि 'इसे छोटा रखने के लिए' ऐसा किया गया।

यह पूछे जाने पर कि क्या जवाब देने वालों के विवरण मीडिया में शेयर किए जा सकते हैं, घनवत ने कहा, 'वे सुप्रीम कोर्ट के पास उपलब्ध हैं और वे इसे बाद में साझा कर सकते हैं।' इस बारे में दबाव डाले जाने पर उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं मालूम कि यह डेटा किसके पास है? जिसके पास यह है, वह आगे आकर इसे जारी करे। आप ऊध के अंतर्गत इसकी मांग कर सकते हैं।' कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों के संदर्भ में घनवत ने कहा, 'यदि ये लोग अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे तो इन्हें समिति के पास आना चाहिए था।'

यह पूछने पर कि समिति प्रदर्शन स्थल तक क्यों नहीं गई जहां ये किसान नवंबर 2020 से डेरा डाले हुए थे, उन्होंने कहा, 'यह गणतंत्र दिवस के आसपास की बात है।।सुरक्षा को लेकर मुद्दे थे, ऐसे में हम प्रदर्शन स्थल नहीं जा सकते थे।' हालांकि घनवत ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि रिपोर्ट प्रतिनिधित्व करने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमारी जिन 73 संगठनों से बात हुई, उसमें से 61 ने कुछ सुझावों के साथ कृषि कानूनों का समर्थन किया। 15 से 16 संगठनों ने ही कहा कि वे कानूनों को निरस्त करने के पक्ष में हैं।' उन्होंने कहा, 'जिन किसानों को हमने आमंत्रित किया, उसमें से कई कोविड के कारण आने में असमर्थ थे। कई अन्य के नेटवर्क इश्यु (जब ऑनलाइन इंटरव्यू का सुझाव दिया था)थे, ऐसे में हम उनके विचार नहीं जान सके।' 20 हजार से अधिक के मिले ऑनलाइन रिस्पांस में से केवल 5000 जवाब देने वाले ही किसान थे।

जन हितैषी

सकते में दुनिया

रूस और यूक्रेन की जंग को एक माह पूरे होने को हैं। इस अवधि में रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई में क्या हासिल हुआ इस पर लंबे समय तक बहस होती रहेगी। मगर अभी रूस और अमेरिका की दादागिरी में यूक्रेन का जो हाल हो रहा है, वह सभी के लिए सबक है, खासकर छोटे देशों के लिए। यूक्रेन आज लगभग खंडहर जैसा नजर आ रहा है। रही-सही कसर कीव पर टिकी है। मगर इस भूभाग पर कब्जा जमाने रूस कोई भी पैंतरा आजमाने को तैयार बैठा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब परमाणु हथियारों वाली कमान को तैयार रहने का निर्देश देकर अपना इरादा साफ कर दिया है कि उन्हें अब किसी का डर नहीं। इससे दुनिया के ज्यादातर देश सकते में हैं। खासतौर से अमेरिका और यूरोपीय संघ के उन देशों की नींद उडऩा लाजिमी है जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और उसे रूस से मुकाबला करने के लिए हथियार दे रहे हैं। इससे अब यह खतरा पैदा हो गया है कि हालात कब क्या मोड़ ले लें और पुतिन परमाणु हमले का दांव न चल दें। रूस ने अमेरिका, पश्चिमी देशों तथा नाटो की धमकियों के बाद जिस तरह का आक्रामक रुख अख्तियार किया है, उससे खतरा और बढ़ गया है। जंग शुरू होने से पहले तक तो लग रहा था कि अगर लड़ाई छिड़ भी गई तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। पर रूस के धावा बोल देने के बाद पिछले पांच-छह दिन में हालात जिस तेजी से बिगड़े हैं, उसे देखते हुए कोई भी कयास लगा पाना आसान नहीं है। भले ही यूक्रेन की सैन्य ताकत रूस के मुकाबले कम हो हो, लेकिन उसका मनोबल कहीं ज्यादा बड़ा दिख रहा है। निश्चित ही यह पुतिन के लिए एक बड़ा संदेश भी है। संभव है कि परमाणु हमले की धमकी यूक्रेन को दबाव में लाने के लिए ही दी गई हो। हालांकि रूस यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। लेकिन जो भी हो, परमाणु हमले की धमकी देकर रूस ने बता दिया है कि यूक्रेन को लेकर अब वह जो भी करेगा, अपनी शर्तों पर ही करेगा। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सनक का नतीजा दुनिया भुगत चुकी है। गौरतलब है कि दूसरे विश्वयुद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिरा कर दुनिया को इसके अंजाम के बारे में बता दिया था। उस तबाही की यादें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। हालांकि, अभी रूस के हमले से सिर्फ यूक्रेन पस्त है, ऐसा नहीं है। वहीं, रूस-यूक्रेन की जंग का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में घटनाएं क्या मोड़ ले लें। संकट इसलिए भी गहराता जा रहा है कि जंग लड़ रहे दोनों देश कच्चे तेल, गैस और गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। यूरोप सहित कई अन्य देश भी इनसे गैस और तेल खरीदते हैं। गेहूं और निकल, एल्युमीनियम जैसी धातुओं के दाम भी पिछले पांच दशक के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। रूस और यूक्रेन दुनिया का चौदह फीसद गेहूं पैदा करते हैं। ऐसे में महंगाई कहां जाएगी, कोई नहीं जानता। युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराने को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि ज्यादातर देश महामारी की मार से अभी तक उबरे भी नहीं थे कि दूसरा संकट सिर पर आ गया। युद्ध और महामारी जैसी विपत्तियां मानव जीवन को कैसे तबाह कर देती हैं, यह अब छिपा नहीं रह गया है। महामारी की वजह से महंगाई और बेरोजगारी ने किसको नहीं रुलाया! अब फिर वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। रोजाना नए रिकार्ड बनाता कच्चा तेल सबसे बड़ा संकट पैदा कर रहा है। कच्चा तेल महंगा होते ही सरकारें पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का कदम उठाती हैं और इसका सीधा हर तरह के कारोबार से लेकर आम जीवन पर पड़ता है। भारत दुनिया के कई देशों को दवाइयों से लेकर कपड़े, मशीनें, कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाय, कॉफी, वाहन आदि का निर्यात करता है। साथ ही दालें, खाने के तेल, उद्योगों के लिए कच्चा माल आयात करता है। वैश्विक कारोबार में हर देश इसी तरह एक दूसरे के सहारे टिका हुआ है। ऐसे में महंगा कच्चा तेल नौवहन की लागत बढ़ाता है और फिर इसका असर निर्यात-आयात पर पड़ता दिखता है। लागत बढ़ने से स्थानीय कारोबारी प्रभावित होते हैं और महंगाई बढ़ती है। रूस को वैश्विक भुगतान व्यवस्था से अलग-थलग कर देने के बाद कारोबारियों को पैसे फंसने का भी डर सता रहा है।

भाजपा की सांस्कृतिक अधिष्ठान की जीत

देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में प्राप्त हुई विजय ने सिद्ध कर दिया है कि यह भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे की विजय है। जनता ने भाजपा में विश्वास जताया है, भाजपा की नीतियों का समर्थन किया है। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, क्योंकि यही चुनाव आगे के लोकसभा चुनाव की दिशा निर्धारित करता है। यह चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। उनका दावा था कि राज्य की जनता उनके विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें पुनः सत्ता का बागडोर सौंपेगी। उनका यह दावा सत्य सिद्ध हुआ।

कारण स्पष्ट है कि भाजपा अपने चाल चरित्र, चेहरे के अनुसार निरंतर हिंदुत्व की छवि को और सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। प्राचीन शहरों के नाम बदलना तथा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण इसका उदाहरण है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। सरकार नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल करने पर विशेष बल दे रही है। गंगा का प्रदूषण कम करने के लिए स्मार्ट गंगा सिटी परियोजना पर कार्य जारी है। योगी सरकार राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना प्रारम्भ की गई है।

चार राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में मिली विजय से भाजपा नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में अपार हर्षोल्लास है। भाजपा इस विजय रथ को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। भाजपा लगभग साढ़े तीन दशक के पश्चात पहली बार उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार में आई है। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी पहली बार भाजपा सरकार दोहराई गई है। गोवा में तो विजयश्री की हैट्रिक लगी है। भाजपा को प्रत्येक दिशा से अपार जनसमर्थन मिला है। इस विजय ने 2024 के परिणामों को लगभग निश्चित कर दिया है। वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 325 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। उस समय चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था। इस बार भाजपा ने 255 सीटों पर विजय प्राप्त की है, परन्तु पिछली बार की तुलना में भाजपा को 57 सीटों की हानि हुई है। किन्तु भाजपा ने इस बार उत्तर प्रदेश में लगभग 42 प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसे 39.67 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ाना पार्टी नेताओं के लिए हर्ष का विषय है, परन्तु लोकसभा चुनाव में विजय का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भाजपा को अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगभग 50 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। इस दृष्टि से देखा जाए, तो भाजपा को लोकसभा चुनाव में अपने घटे मत प्रतिशत को पुनः प्राप्त करने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा।

उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे लगभग 28 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने 32 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किए हैं, जो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। इस बार सपा ने 111 सीटें प्राप्त की हैं। इस प्रकार उसे 64 सीटों का लाभ हुआ है। बहुजन समाज पार्टी से भाजपा को कोई विशेष खतरा नहीं है, क्योंकि बसपा के मतदाता अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मायावती ने उनके नाम पर केवल सत्ता प्राप्त कर उसका सुख भोगा। उन्हें दलित समाज के दुःख-सुख से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए इस बार बसपा को केवल एक ही सीट से संतोष करना पड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में उसे 18 सीटों की हानि हुई है। कांग्रेस की बात करें, तो पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी के वर्षों के कड़े प्रचार के पश्चात भी उसे केवल दो ही सीटें प्राप्त हो सकीं। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में उसे पांच सीटों की हानि हुई है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता भी नहीं बचा, जो उसके लिए विजय का मार्ग प्रशस्त कर सके। कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में दिखाई नहीं देती। पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के प्रचार के पश्चात कांग्रेस केवल सात ही सीटें जीत पाई थी।

इस बार के विधानसभा चुनाव ने कई मिथक तोड़े हैं। विपक्षी दल जिन मुद्दों को सरकार के विरुद्ध मान रहे थे, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने एक लंबे समय तक आंदोलन किया। देशभर में प्रदर्शन हुए और रैलियां निकाली गईं। विपक्षी दलों ने खुलकर किसानों का समर्थन किया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों का साथ दिया। इसके पश्चात भी पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुनकर राजनीति में एक नये अध्याय का प्रारंभ किया। स्थिति तो यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट तक नहीं बचा पाए।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी व अन्य दलों ने किसान आन्दोलन का समर्थन किया था। अखिलेश यादव को विश्वास था कि माय अर्थात मुस्लिम और यादवों के वोट बैंक के साथ उन्हें जाटों का भी भरपूर समर्थन मिलेगा, इसलिए उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुभासपा और अपना दल जैसे कई छोटे दलों से भी गठबंधन किया,

परन्तु गठबंधन सफल नहीं हुआ। भाजपा ने किसान आन्दोलन के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों में से 93 पर विजय प्राप्त करके सिद्ध कर दिया कि किसान आन्दोलन निष्प्रभावी रहा। साथ ही लखीमपुर खीरी की उन आठ विधानसभा सीटों पर भी भाजपा ने विजय पाई, जो उसके लिए कठिन मानी जा रही थीं।

वास्तव में भाजपा की विजय भाजपा की नीतियों और उसकी सरकार के विकास कार्यों की विजय है। उत्तर प्रदेश मंह योगी श्री आदित्य नाथ ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के पश्चात राज्य में विकास कार्यों की गंगा बहा दी।

राज्य में बेघरों को आवास देने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना प्रारम्भ की गई। निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आरम्भ की गई। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान प्रारम्भ किया गया। बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई। राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना प्रारम्भ की गई। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता नामक योजना आरम्भ की गई।

राज्य के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ देने के लिए श्रमिक पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई। श्रमिकों के भरण पोषण के लिए राज्य में श्रमिक भरण पोषण योजना आरम्भ की गई है। इसके साथ ही राज्य की समृद्धि के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया है। राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए परम्परागत खेती विकास योजना चलाई जा रही है। खेतों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना तथा उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना संचालित की जा रही है। इनके अतिरिक्त बीज ग्राम योजना के अंतर्गत किसानों को धान एवं गेहूं के बीज पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। पारदर्शी किसान सेवा योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को समुचित उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। किसानों को ऋण के बोझ से मुक्त करने के लिए किसान ऋण मोचन योजना प्रारम्भ की गई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

राज्य में अनाथ बच्चों को आसरा देने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गई। महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की पुत्रियों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत पुत्री की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त लोगों को घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग संवाददाता सखी योजना प्रारम्भ की गई है। इससे जहां लोगों को घर पर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वहीं महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त हुआ है।

राज्य में अनेक पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना तथा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पेंशन योजना सम्मिलित हैं। सरकार लड़कियों और दिव्यांगों के विवाह के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत लड़कियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के विवाह लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रही है। राज्य में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों एवं उनके नये भवनों की स्थापना की जा रही है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किय जा रहा है। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ सिटी योजना प्रारम्भ की गई है। विद्युत क्षेत्र में भी योगी सरकार उत्कृष्ट कार्य किया है। परिवहन के क्षेत्र में भी सरकार ने सराहनीय कार्य किए हैं। राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की है।

योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि अपने कार्यकाल में राज्य में रोजगार के अवसर तीव्रगति से बढ़े हैं। स्टार्टअप नीति के अंतर्गत पांच लाख युवाओं को रोजगार मिला है, जबकि मनरेगा के माध्यम से डेढ़ करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक करोड़ महिलाओं को रोजगार मिला है। इतना ही नहीं साढ़े चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई, जबकि साढ़े तीन लाख युवाओं की संविदा पर नियुक्ति हुई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को 2.16 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। निःसंदेह भाजपा अपने विकास कार्यों के कारण ही पुनः सत्ता में आई है। (लेखक- डॉ. सौरभ मालवीय/ईएमएस)

कश्मीर फाईल सच और झूठ

भारत में झूठ बोलने वाली शक्तियां अफवाहें फैलाने में इतनी सक्षम हो चुकी हैं कि वे बिल्कुल निकट के इतिहास पर भी अफवाहों और झूठ की धूल फेंक कर अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी से बच निकलती हैं।वे उन लोगों को बदनाम करती हैं जिन्हें बाद में बदतर हालातों को सामान्य बनाने में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अफवाह फैलाने वाली ये शक्तियां अगर अपने घृणित मंसूबों में सफल होती रहीं तो शायद लोकतंत्र के समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा ।आज जरूरत है कि हमने 75 साल में जिस लोकतंत्र को विश्व के सामने एक उच्च मानवीय उदाहरण की परिपक्वता के रूप में स्थापित किया है उसे हम सब मिलकर जहरीले वातावरण से बाहर निकालें।

आज 32 साल पुरानी कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी को फिर से सुर्खियों में लाने की चेष्टा

की जा रही है। फिर आधे आधे अधूरे घटनाक्रम को चित्रित कर एक फिल्म कश्मीर फाइल के माध्यम से इस दुष्प्रचार अभियान को स्थापित किया जा रहा है जिसके तथ्यों में इतनी असत्यता है कि एक सैन्य अधिकारी की पत्नी को उसके शहीद पति का झूठा चित्रण करने के कारण फिल्म निर्माता पर मुकदमा दायर करना पड़ा है। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन और संहार एक राष्ट्रीय त्रासदी है मानवता पर एक बर्बर हमला है, लेकिन इसके दोषी कौन हैं?उनकी असलियत क्या है ?

कश्मीर में 1989 में टीकालाल टप्लू की

हत्या से यह अनाचार शुरू हुआ ।तब केंद्र में भाजपा समर्थित वी पी सिंह सरकार थी , केंद्र में कश्मीरी गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। जब भी कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की

कहानी सामने लायी जाती है, तो कुटिल बुद्धिजीवी इन तथ्यों को छुपाते हैं। वे वास्तविक घटनाओं को सामने नहीं रखते। न ही उन लोगों की चर्चा करते हैं, जो उस समय जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हुए थे तथा कानून व्यवस्था के लिये सीधे जिम्मेदार थे।

कश्मीर में सबसे जघन्य घटना 19 जनवरी 1990 को घटित हुई थी जब कश्मीरी पंडितों पर जानबूझकर और चिन्हित कर कर के हमले किए गए थे। उन्हें मजबूर किया गया था कि वे अपना घर और घाटी छोड़ दें। जब यह घटनाएं घट रही थी तब गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद संभालने में असफल रहे और राज्यपाल जगमोहन के नेतृत्व में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आगे जाकर यही जगमोहन भाजपा की अटल सरकार में शहरी विकास मंत्री बने। यानि जब कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए थे ,तब जो लोग इसे रोक सकते थे ,वे या तो भाजपा समर्थित सरकार के गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे ,बाद में जिनकी बेटी रूबिया की रिहाई के बदले में सरेआम आतंकी छोड़े गए थे या राज्यपाल जगमोहन जो उस समय राष्ट्रपति शासन के सर्वेसर्वा थे। वे अपने आपको कश्मीर की समस्याओं के विशेषज्ञ के रूप में प्रचारित भी करते थे । सबसे सक्षम व्यक्ति होते हुये भी वे इस नरसंहार को रोकने या उस पर काबू पाने या कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में बुरी तरह असफल हुए । कह सकते हैं कि वे उदासीन थे ।जब स्थितियां नियंत्रण से बाहर और भयावह हो गई ,तब अंततः उन्हें 26 मई 1990 को हटाना पड़ा।

दूसरी ओर मुफ्ती मुहम्मद सईद भी कश्मीर के बिगड़े हुए हालातों पर काबू पाने की बजाय, अलगाववादियों के समर्थक के रूप में उभरे। आगे जाकर इन्हीं मुफ्ती साहब के नेतृत्व में भाजपा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सरकार बनी जिसमें 2015 में वे मुख्यमंत्री बने।भाजपा ने यह आज तक स्पष्ट नहीं किया है कि उसने किस मजबूरी में इस नरसंहार के जिम्मेदार तत्कालीन गृहमंत्री को अपना मुख्यमंत्री मान लिया ।उसके साथ मिलकर सरकार बनाई। क्या यह कश्मीरी पंडितों के दुःख और त्रासदी का भद्दा मजाक नहीं था ?

अगर इतिहास में झांकें तो आजादी मिलने के पहले भी 1931 में डोगरा हिन्दुओं पर कश्मीर में व्यापक रूप से हमला हुआ था। उन्हें लूटा गया था ,उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। तब वहां डोगरा राजा हरी सिंग का राज था। उसके बाद 1947 में भी ये हमले फिर हुए तब कश्मीर की कुल आबादी में डोगरों की संख्या 15 प्रतिशत थी।जिसमें पाकिस्तानी सेना के लोग प्रमुख रूप से शामिल थे।तब राजा हरिसिंह असमंजस में थे कि वे अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करें या भारत में ।

वे इस आशय का पत्र पाकिस्तान सरकार को दे भी चुके थे कि वे पाकिस्तान में शामिल होंगे किंतु उसे उन्होंने होल्ड पर रखा था। तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। जब हमला हुआ था, उस समय तक राजा हरिसिंह भारत में विलय का मन नहीं बना पाए थे। लेकिन जब रियासत को बचा पाना उनके बूते से बाहर चला गया, तब उन्होंने भारत से सहायता की याचना की और भारत में विलय की मंशा जाहिर की। राजा हरिसिंह की सहमति मिलते ही भारत की सेना ने कश्मीर कूच किया । तब तक पाकिस्तानी सेना मिश्रित कबायली हमलावर श्रीनगर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुके थे। भारत के बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तानियों को खदेड़ा और श्रीनगर पर नियंत्रण को स्थापित किया। आगे क्या हुआ यह इतिहास का वह हिस्सा है, जिसे सभी जानते हैं।

कश्मीरी पंडितों पर 1990 के बाद उस समय फिर से तीखे हमले हुए,जब 7 पंडितों को संग्रामपुरा में निर्दयता से मारा गया । तब भी केंद्र में देवेगौडा की सरकार थी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के ओर से इन्द्रजीत गुप्ता गृह मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद देश में 2 और बड़े हमले कश्मीरी पंडितों पर 1998 से 2003 के बीच में हुए। जिनमें क्रमशः 23 और 24 पंडितों की हत्या

की गयी। इन दोनों घटनाओं के समय भी अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार थी तथा लालकृष्ण आडवानी गृह मंत्री थे। ये घटनाएँ बताती हैं कि कश्मीरी पंडितों पर हुए सबसे बड़े हमले में

जिसमें लगभग साढ़े तीन लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे और लगभग 300 लोग मारे गए थे, से लेकर 2003 तक की घटना तक, जिसमें 24 पंडितों की हत्या की गयी, कश्मीर में भाजपा या उसकी समर्थित सरकारें ही निर्णायक सरकारों का हिस्सा थीं। तब इस नरसंहार के लिए कांग्रेस को क्यों जिम्मेदार बताया जा रहा है? इन नरसंहारों की जिम्मेदारी लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी बाजपेयी, मुफ्ती मुहम्मद सईद या जगमोहन की ही थी। ये वही लोग हैं, जो घटना के समय सीधे सत्ता में थे और अमन कायम करना इनकी पहली जिम्मेदारी थी।

हैरानी की बात तो यह है कि जब अटलबिहारी सरकार में लालकृष्ण आडवानी गृह मंत्री थे, तब 11 जून 1999 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कश्मीर में इस नरसंहार की जाँच करने भेजा गया था। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ठइसके बावजूद कि कश्मीरी पंडितों पर ज्यादतियां हुयीं हैं, यह मात्र अत्याचार ही था, इसे जनसंहार (जेनोसाइड) नहीं माना जा सकता।ठ आज कितने कश्मीरी यह बात समझने के लिये तैयार हैं कि यह निष्कर्ष टीकालाल टप्लू, जस्टिस नीलकांत गंजू, कवि सर्वानन्द कौल, एडव्होकेट प्रेमनाथ भट्ट तथा लासा कौल के बलिदान को अपमानित करने वाला निष्कर्ष है। क्या तत्कालीन भाजपा सरकार ने इन निष्कर्षों पर अपनी आपत्ति दर्ज करायी थी ? नहीं करायी ! तो क्यों ? क्या यह भी सच नहीं है कि राज्यपाल जगमोहन जिस सरकार के प्रमुख थे, उसने अधिकृत तौर पर केवल 219 पंडितों की ही हत्या को स्वीकार किया था, जबकि कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति 399 पंडितों की हत्या को मानती है। एक अन्य सर्वेक्षण हत्या के आंकड़े को 302 मानता है। फिर किन तथ्यों के आधार पर भाजपा और संघ के नेता इस संख्या को कई लाखों में प्रचारित कर देश को

भ्रमित करते घूमते रहे हैं। यह शोध का विषय है। जब भी इन अराजक परिस्थितियों के बाद आई अन्य सरकारों ने परिस्थितियों को सामान्य बनाने में अपनी ताकत लगायी, तो उल्टे उन्हें ही बदनाम किया गया। कश्मीर के हालातों को पुनः बदतर बनाया भाजपा और मेहबूबा मुफ्ती ने क्योंकि जिन अराजक पत्थर गेंग को पूर्व सरकारों ने जेल में डाला हुआ

था, उन्हें मुफ्ती-मोदी सरकार के आते ही जेल से छोड़ दिया गया । उन्हें पुनः संगठित होने का भरपूर मौका और पोषण मिला। जिन्हें जेल से छूटकर वे छोटे सी समयावधि में इतने संगठित हो गए कि बुरहान बानी की अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए। क्या जाँच नहीं होना चाहिए कि इतनी जल्दी वे इतनी ताकत जुटाने में कैसे सफल हुए? कि राष्ट्रवाद का दम भरने वाले नेता ही बुरहान वाणी की मौत को धोखे में उठाया गया कदम बताने लगे? क्या भाजपा के उपमुख्यमंत्री यह नहीं कह रहे थे कि अगर पता होता कि बुरहान वहां है तो वे विकल्प पर विचार करते।क्या यही उनका तथाकथित राष्ट्रवाद है ? या ये तथाकथित राष्ट्रवादी देशद्रोहियों के सामने घुटना टेक हो चुके थे ? आज देश को यह विचारने की आवश्यकता है कि समय जो घाव भर देता है उसे झूठ के चाकू से कुरेदा जाना व्यापक समाज के संतुलन पर हमला है जो संभवतः आगामी चुनावों की चौसर पर बिछाया जा रहा है। (लेखक-भूपेंद्र गुप्त/ ईएमएस)

शब्द पहेली - 7233

बाएँ से दाएँ

1.ईश्वरीय कृपा-4
4.कुंए पर पानी भरने का चबूतरा-4
6.दुर्बल का विलोम-3
8.सुनसान,नीरव-3
9.प्रेम प्रतिद्वंदी (उर्दू-3)
11.घोषवाक्य-2
13.चित्रपट,मायानगरी -3,2
15.सूर्य,भास्कर-2
16.उपनदी,कैनाल-3
18.व्यंग,परिहास-3
19.कौर,ग्रास-3
20.दफन करना-4
22.भूल,असावधानी-4

ऊपर से नीचे

1.अगुवा,रास्ता दिखाने वाला-4
2.सरुर,नशा,गरुर-2
3.चिंतन,विचारना-3
4.परजन भावना,गैरपन-5
5.भिड़ना,मुठभेड़-4
7.रेखा,लाईन-3
10.झाग बनना-5
12.सीमा,हद,बॉर्डर-4
14.शाखा,डाली-3
17.रिवाज,परंपरा-4
18.पाबंदी,रोक-3
21.स्वच्छ-2

शब्द पहेली -7232 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

आज का इतिहास 23 मार्च

1351 फिरोजाबाद तुगलक का भतीजा मुहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा था.
1568 फ्रांस में दुसरा धर्म युद्ध समाप्त हुआ.
1757 क्लाइब ने फ्रांसिसियों से छीन लिया.
1910 समाजवादी चिंतक राममनोहर लोहिया का जन्म.
1918 लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की.
1931 भगतसिह,सुखदेव और शिवराम राजगुरू को साडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दी गई.
1933 एडोल्फ हिटलर को तानाशाह के रूप में सारे अधिकार मिल गए.
1936 इटली सोवियत संघ और हंगरी के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ.
1940 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया.
1976 भारत-श्रीलंका सीमा समझौता.
1986 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली महिला कंपनी का गठन दुर्गापुर मे हुआ.
1986 पाकिस्तान में लाखों लोगों ने सरकार और अमेरिका विरोधी प्रदर्शन किया.
1991 राष्ट्रव्यापी विद्रोह के बीच सद्दाम हुसैन ने इराकी मंत्रीमंडल में भारी फेरबदल किया.
1992 उत्तरप्रदेश सरकार के विरूद्ध संविधान की धारा 356 की कार्यवाही की केन्द्र की चेतावनी.

खेल - समाचार

बांग्लादेश पर जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंची

हैम्लिटन (ईएमएस)। आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ मिली 110 रनों की शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गयी हैं।

इस जीत के साथ ही भारतीय टीम अब अंक तालिका में वेस्टइंडीज को पीछे करते हुए तीसरे स्थान पर आ गयी है। भारतीय टीम ने अब तक 6 मैच खेले हैं। इसमें उसे 3 में जीत और इतने ही मुकाबले में हार मिली है। भारत के कुल 6 अंक हैं। इस जीत के बाद भारत का नेट रन रेट 0.768 हो गया है, जो दूसरे स्थान पर कायम दक्षिण अफ्रीका (0.092) से भी बेहतर है.

वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट में लगातार छठी के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंच गयी है। ऑस्ट्रेलिया के 12 अंक हैं. वहीं दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका के 5 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक है और उसका भी सेमीफाइनल में जगह बनाना तय है। वहीं भारतीय टीम को अपना अंतिम लीग मुकाबला 27 मार्च को दक्षिण अफ्रीका से खेलना है। अगर भारतीय टीम यह मुकाबला जीत लेती है तो फिर उसके 7 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक हो जाएंगे और टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी हालांकि, अगर भारत यह मुकाबला हार जाता है, तो फिर उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बाकी लीग मुकाबलों के परिणामें पर निर्भर रहना होगा।

वेस्टइंडीज की स्थिति भी भारत जैसी है, उसने भी 6 मैच में से 3 जीते हैं पर उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी लीग मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अभी वेस्टइंडीज की टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर है पर टीम की सबसे बड़ी परेशानी उसका नेट रनरेट है। कैरेबियाई टीम का नेट रनरेट (-0.885) है. वहीं, इंग्लैंड की टीम अंक तालिका में पांच मैच में 2 जीत और तीन हार के साथ पांचवें स्थान पर है। इंग्लैंड भी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई है। अगर इंग्लैंड टीम अपने आखिरी दोनों लीग मैच जीत लेती है, तो उसके भी 8 अंक हो जाएंगे। ऐसे में सेमीफाइनल की दौड़ और रोमांचक हो जाएगी और फिर नेट रन रेट से फैसला होगा। वहीं मेजबान न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कम है। टीम ने 6 मैच में से 2 ही जीते हैं और टीम अंक तालिका में 4 अंक के साथ छठे स्थान पर है।

आईसीसी रैंकिंग : मंधाना की शीर्ष दस में वापसी

दुबई (ईएमएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की महिला एकदिवसीय रैंकिंग में भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना एक बार फिर से शीर्ष दस में पहुंच गयी हैं। मंधाना के अब 663 रेटिंग अंक हो गये हैं। अब वह एक स्थान के लाभ के साथ ही दसवें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं कप्तान मिताली राज को खराब प्रदर्शन का नुकसान हुआ है ओर वह एक स्थान नीचे आकर सातवें से आठवें नंबर पर फिसल गयी हैं।

मंधाना ने मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्वकप में 30 रनों बनाये थे। मंधाना के अलावा कप्तान मिताली के 696 रेटिंग अंक हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी अब एक पायदान नीचे खिसकर सातवें नंबर पर पहुंच गयी हैं। झूलन के 674 रेटिंग हैं। गेंदबाजी में शीर्ष दस में शामिल एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ चार विकेट लेने वाली स्नेह राणा 49वें जबकि दीप्ति शर्मा 17वें और राजेश्वरी गायकवाड़ 14वें नंबर पर हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड की सोफी एक्सलेस्टॉन शीर्ष पर हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया की जीस जोनासन दूसरे और मेगन शट्टी तीसरे स्थान पर बनी हुई हैं।

बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की एलीस हीली 730 रेटिंग अंकों के साथ ही नंबर एक पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की ही बेथ मूनी दूसरे जबकि दक्षिण अफ्रीका की लौरा वॉलवार्ट तीसरे और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लैनिंग चौथे नंबर पर पहुंच गई हैं।

आईसीसी महिला विश्व कप : लैनिंग के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठा मुकाबला जीता

वेलिंगटन (ईएमएस)। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। मेग लैनिंग के शानदार शतक से ऑस्ट्रेलिया ने अपने छठे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को पांच विकेट से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत के लिए 272 रनों का लक्ष्य दिया। जिसे ऑस्ट्रेलिया ने लैनिंग के नाबाद 135 रनों की सहायता से 45.2 ओवर में ही 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।

इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम की सेमीफाइनल में जगह तय हो गयी है। उसके इस मुकाबले जीत से 6 मैचों में 12 अंक हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका इस विश्व कप में पहली बार हारी है। अब दक्षिण अफ्रीका की टीम 5 मैचों से 8 अंक के साथ ही दूसरे नंबर पर है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाज लॉरा वॉल्वार्ट और कप्तान सुन लुस की अर्धशतकीय पारी की सहायता से 5 विकेट पर 271 रन बनाए। वॉल्वार्ट ने 134 गेंदों पर 90 रन की पारी खेली जबकि लुस ने 51 गेंदों पर 52 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मेगन शट, जोनासेन, गार्डनर, सदरलैंड और अलाना किंग ने एक एक विकेट लिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 45 रनों पर ही अपने शुरुआती विकेट खो दिये। इसके बाद मेग लैनिंग ने अन्य बल्लेबाजों के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। लैनिंग 130 गेंदों पर 135 रन बनाकर नाबाद रहीं।

लैनिंग और बेथ मूनी के बीच तीसरे विकेट के लिए 60 रन जबकि तहिलिया मैक्ग्रा और लैनिंग के बीच चौथे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी हुई। मैक्ग्रा लैनिंग और एश्ले गार्डनर के बीच 43 रन की साझेदारी हुई वहीं सदरलैंड के साथ पांचवें विकेट के लिए दोनों ने नाबाद 31 रन बनाये।

मिताली के नाम हुआ एक अनचाहा रिकार्ड

हैमिल्टन (ईएमएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट मुकाबले में अबतक लय में नहीं आयी है। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भी मिताली पहली ही गेंद पर शून्य पर ही आउट हो गयी। इसी के साथ मिताली के नाम एक ऐसा रिकार्ड जुड़ गया जिसे वह याद नहीं रखना चाहेंगी। मिताली यहां खेले गए मैच के दौरान विश्व कप में दूसरी बार गोल्डन डक का शिकार हुई हैं। मिताली इससे पहले साल 2017 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी गोल्डन डक का शिकार हुई थी। इस प्रकार वह टूर्नामेंट के इतिहास में 2 बार डोल्डन डक का शिकार होने वाली पहली कप्तान हैं। इसके अलावा वह पहली और एक मात्र भारतीय कप्तान भी हैं जो महिला विश्व कप में डोल्डन डक हुई हैं। इससे पहले मिताली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ एक रन बनाया था जबकि पाकिस्तान के खिलाफ वह 31 रन ही बना पायीं। अब तक विश्व कप में वह केवल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 68 रन बना पायी हैं।

आईसीसी महिला विश्वकप : भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 110 रनों से हराया

हैमिल्टन (ईएमएस)। भारतीय टीम ने आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप क्रिकेट के अपने छठे मैच में बांग्लादेश पर 110 रनों से बड़ी जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यास्तिका भाटिया के शानदार अर्धशतक 50 रनों की सहायता से सात विकेट पर 229 रन बनाए। इस प्रकार बांग्लादेश को जीत के लिए 230 रनों का लक्ष्य मिला जिसका पीछा करते हुए उसकी पूरी टीम 40.3 ओवर में 119 रनों पर ही आउट हो गयी।

230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसकी कोई भी बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पायी। सलमा खातून 32 , लता मंडल 24 , मुशहिदा खातून 19 और रितू मोनी 16 के अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज दो अंकों तक भी नहीं पहुंच पायी।

भारत की ओर से स्नेह राणा ने 4 जबकि झूलन गोस्वामी और पूजा वस्त्राकर ने 2-2 विकेट लिए। इस मैच में जीत के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गयी हैं। भारतीय टीम अभी छह मैचों में 3 जीत और तीन हार के साथ ही अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश टीम 5 मैचों में 2 जीत के साथ 7वें स्थान पर खिसक गयी है।

इससे पहले भारतीय पारी की शुरुआत करते हुए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अच्छी शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े। इसके बाद तीन विकेट गिरने से रन गति पर अंकुश लग गया। दोनों सलामी बल्लेबाज और फिर कप्तान मिताली राज भी भी बिना कोई रन बनाये पेवेलियन लौट गयीं। अनुभवी बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर भी 14 रनों पर ही रन आउट हो गयीं और बड़ा स्कोर नहीं बना पायीं। इसके बाद पूजा वस्त्राकार 30 , स्नेह राणा 27 और ऋचा घोष 26 ने रन बनाये भारतीय टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत की ओर से यास्तिका भाटिया ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाये। इस प्रकार इस बल्लेबाज ने विश्वकप में अपना दूसरा दूसरा अर्धशतक लगाया। स्मृति मंधाना ने 30 जबकि शैफाली वर्मा ने 42 रन बनाये। हभारतीय पारी के 43वें ओवर में यास्तिका ने पचासा पूरा किया। वहीं कप्तान मिताली राज अपना खाता भी नहीं खोल पायीं। बांग्लादेश की ओर से रितु मोनी ने तीन जबकि नाहिदा अख्तर ने दो। वहीं जहांआरा आलम ने एक विकेट लिया।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुंबई (ईएमएस)। मुम्बई शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में यह उछाल रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में लिवाली (खरीददारी) से आया है। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 696.81 अंक करीब 1.22 फीसदी बढ़कर 57,989.30 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 197.90 अंक तकरीबन 1.16 फीसदी की बढ़त के साथ ही 17,315.50 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के तीस शेयरों में से टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, टीसीएस, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस और पावर ग्रिड के शेयर सबसे ज्यादा फायदे में रहे। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर लि., नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी और सन फार्मा के शेयर गिरे हैं। बाजार जानकारों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और फेडरल रिजर्व के आक्रमक रुख को देखते हुए बाजार की शुरुआत अच्छी नहीं रही पर इसके बाद यूरोपीय बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों से बाजार ऊपर आने लगा।'' शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे। उन्होंने सोमवार को 2,962.12 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे। इससे पहले सुबह बाजार हल्की बढ़त के साथ खुला पर समय के साथ ही इसमें सुधार आने लगा।

चीन में भारत के नए राजदूत रावत ने एससीओ महासचिव से मुलाकात की

बीजिंग (ईएमएस)। चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप के. रावत ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महासचिव झांग मिंग से मुलाकात कर भारत द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पहलों और आठ सदस्यीय समूह की देश की आगामी अध्यक्षता पर चर्चा की। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, ''राजदूत प्रदीप के. रावत ने मंगलवार को एससीओ महासचिव झांग मिंग से मुलाकात की।'' इसमें कहा गया है कि दोनों अधिकारियों ने भारत की एससीओ की आगामी अध्यक्षता 2022-23 के साथ ही स्टार्टअप, नवोन्मेष, पारंपरिक औषधि सहित एससीओ में भारत की पहलों पर विस्तार से चर्चा की। भारत ने एससीओ सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप और नवोन्मेष तथा पारंपरिक औषधि जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए नई पहलों का प्रस्ताव दिया है।

भारत को साल 2022 सितंबर से एससीओ संगठन की अध्यक्षता संभालनी है। अभी एससीओ की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के पास है। पहले नीदरलैंड में भारत के राजदूत रह चुके रावत ने इस महीने चीन में राजदूत का प्रभार संभाला है। चीनी राजनयिक झांग ने इस साल जनवरी में एससीओ के महासचिव का पद संभाला। उन्होंने उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री व्लादिमीर नोरोव का स्थान लिया। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है, वह आठ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा समूह है जो सबसे बड़े अंतरक्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक के तौर पर उभरा है। एससीओ की स्थापना रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने 2001 में शंघाई में एक सम्मेलन में की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे।

भारतीय सीमा पर चीन ने गुपचुप आबाद किए 624 'गांव', बढ़ेगी भारत की मुश्किलें

-चीन के राष्ट्रपति ने तिब्बती चरवाहों को सीमा पर बसने का दिया आदेश

बीजिंग (ईएमएस)। भारत-चीन सीमा को लेकर जारी गतिरोध के बीच चीन नित नई चालें चल रहा है अब ड्रैगन ने सीमा पर बसाए जाने वाले 624 गांवों का काम पूरा हो गया है। चीन ने हिमालय की गोद में बनाए गए इन गांवों को निर्माण या तो विवादित सीमा के अंदर या फिर कब्जा किए हुए इलाकों में किया है। चीन ने इन सैन्यीकृत गांवों का निर्माण कार्य साल 2017 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर शुरू किया था। चीन सरकार ने अपने दस्तावेज में खुलासा किया था कि कुल 624 गांव बनाए जाने हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने चीन की सरकारी वेबसाइट के हवाले से बताया कि चीन की सरकार ने साल 2021 में इन गांवों का निर्माण कार्य पूरा किया है। चेलानी ने कहा कि भारत चुनावों और घरेलू राजनीति में व्यस्त है। वहीं चीन ने चुपके से भारत से लगती सीमा पर ये 624 गांव बसाने का काम पूरा कर डाला है। उन्होंने कहा कि साल 2017 में चीन के राष्ट्रपति ने तिब्बती चरवाहों को सीमा पर बसने का आदेश दिया था। इसके बाद से इन गांवों को बसाने का काम तेज हो गया।

चीन का दावा है कि तिब्बत स्वायत्त इलाके में बनाए गए इन सभी 624 गांवों में बिजली, इंटरनेट, पानी और मजबूत सड़क बनाई गई है। इससे खाने, कपड़े, घर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफी बेहतर हो गई है। चीन का दावा है कि इससे इलाके में समृद्धि, स्थिरता, जातीय एकता और प्रगति आई है। वेबसाइट ने एक ग्रामीण के हवाले से कहा, 'अब हमारे पास बिजली की पहुंच है। सभी इलेक्ट्रानिक उपकरणों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जीवन अब काफी आसान हो गया है।' इन गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा गया है ताकि बिजली की समस्या का समाधान किया जा सके।

चीन ने इन गांवों में बढ़िया मकान और अस्पताल भी बनाए हैं। साथ ही यहां रह रहे लोग पैसा कमा सकें, इसके लिए भी इंतजाम करने का दावा किया गया है। यहां बने उत्पादों को चीन के बड़े शहरों में भेजा जाता है। यहां की जरूरत के हिसाब से उद्योग भी लगाए जा रहे हैं। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन ने लोगों को पैसे देकर भारतीय सीमा से लगे इलाकों में बसाया है। भारत- चीन के बीच जारी तनातनी को देखते हुए आम नागरिक इन गांवों में रहने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन चीन इन लोगों को तरह-तरह के लालच देकर फांसने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत से लगी सीमा के नजदीक गांव का निर्माण किया है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये चीनी गांव काफी दूर दराज के इलाके में बनाए गए हैं। इसके अलावा यहां मौसम भी लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में चीन लोगों को लुभाने के लिए सड़कों, पानी, बिजली और कम्यूनिकेशन नेटवर्क को दिखा रहा है। इन लोगों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को देने का ऑफर भी दिया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित थिंक-टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने तिब्बत डेली की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चीन सरकार इन गांवों में रहने के लिए लोगों को प्रति वर्ष 30,000 युआन भी दे रही है। भारतीय मुद्रा में यह राशि करीब साढ़े तीन लाख के आसपास है। इस रिपोर्ट में कई लोगों ने चीन से मिल रहे पैसों को बात को स्वीकार किया है।

तिब्बत मीडिया में बताया गया है कि चीन ने लोगों को बहकाने के लिए बड़ी संख्या में दलालों को भी तैनात किया हुआ है। इस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गाओ ने भी कहा कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक घरों के निर्माण के पीछे बीजिंग है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में त्सारी चू नदी के तट पर दिखाई दिए हैं। भारत के लद्दाख सीमा क्षेत्र के एक पार्षद कोंचोक स्टैनजिन ने कहा कि चीन स्थानीय लोगों को बेहतर रहने की सुविधा प्रदान करके उन्हें लुभाता है ताकि वे विवादित सीमा क्षेत्रों में रहने और स्थायी बस्तियों का निर्माण कर सकें। चीन का जवाब देने के लिए भारत ने अरुचाचल से लेकर देश अन्य हिस्सों पर गांव बसाने शुरू किए हैं। भारत ने सीमा पर गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना का ऐलान भी बजट में किया है। भारत ने कहा है कि सीमावर्ती गांव विरल आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे के अभाव में अकसर विकास के लाभ से वंचित रह जाते हैं। उत्तरी सीमा पर ऐसे गांवों को नए वाइब्रेंट गांव कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। इन गतिविधियों में गांव के बुनियादी ढांचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों की सीधे घर-घर तक पहुंच और आजीविका सृजन के लिए समर्थन देना शामिल होगा।'

सोने, चांदी की कीमतें बढ़ीं

नई दिल्ली (ईएमएस)। घरेलू बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में तेजी आई है। एमसीएक्स पर अप्रैल की डिलीवरी वाला सोना मंगलवार सुबह 0.29 फीसदी करीब 151 रुपये की बढ़त के साथ ही 51,806 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं इसके अलावा जून की डिलीवरी वाला सोना इस समय 0.39 फीसदी तकरीबन 202 रुपये की तेजी के साथ ही 52,152 रुपये प्रति 10 ग्राम पर नजर आया। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी शुरुआती कारोबार में सोने की वायदा और हाजिर दोनों कीमतें बढ़ीं हैं। दूसरी ओर, चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में भी शुरुआती कारोबार में बढ़त आई है। इसके अलावा कच्चे तेल के दाम में भी आज उछाल आया है।

सोने के साथ ही चांदी की वायदा कीमतों में भी शुरुआती कारोबार में बढ़त रही। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में 5 मई 2022 की डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 0.70 फीसद या 478 रुपये की तेजी के साथ 68,827 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखाई दी। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी के वायदा व हाजिर दोनों भाव बढ़त के साथ कारोबाबर करते दिखाई दिए। इसके अलावा क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) की कीमतें भी बढ़ी हैं।

ऊर्जा कीमतों में उछाल के चलते 'फिच' ने भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 8.5 फीसदी किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। रूस-यूक्रेन जंग के चलते ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के बाद रेटिंग एजेंसी 'फिच' ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को 10.3 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि कोरोना वायरस के 'ओमीक्रोन' स्वरूप के प्रकोप में कमी आने के बाद से प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिससे इस साल जून की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि में तेजी लाने के लिए मंच तैयार हुआ है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास के अनुमान को 0.6 प्रतिशत बढ़ाकर 8.7 प्रतिशत कर दिया है। 'फिच' ने कहा, 'हालांकि, हमने भारत के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 में अपने विकास पूर्वानुमान को तेजी से बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण घटाकर 8.5 प्रतिशत (-1.8 फीसदी की कमी के साथ) कर दिया है।'

दो साल के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल-डीजल वाहनों के बराबर होगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे बदलाव और हरित ईंधन के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमत में कमी आएगी और आने वाले दो साल में इनकी कीमत पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों के बराबर होगी। गडकरी ने कहा कि किफायती और स्वदेशी ईंधन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने यह उम्मीद भी जाहिर कि इस तरह का ईंधन जल्द ही वास्तविकता बनेगा और प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। केंद्रीय मंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्रों में सीवेज के पानी का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पहल करें। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जल्द ही सबसे सस्ता वैकल्पिक ईंधन होगा। गडकरी ने कहा कि अधिक से अधिक दो साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी आएगी तथा अगले दो साल में इनकी कीमत पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों के बराबर होगी।

गुजरात ब्लॉक की गैस के लिए न्यूनतम 19 डॉलर प्रति इकाई का मूल्य चाहती है वेदांता

मुंबई (ईएमएस)। वेदांता लि. गुजरात के ब्लॉक से उत्पादित गैस के लिए न्यूनतम 19 डॉलर प्रति इकाई का मूल्य चाहती है। कंपनी का इरादा हाल के समय में ऊर्जा की कीमतों में आए उछाल का लाभ लेना है। वेदांता के निविदा दस्तावेज के अनुसार, कंपनी ने सूरत जिले के सुवाली में स्थित सीबी/ओएस-2 ब्लॉक से उत्पादित 2.5 लाख घनमीटर गैस की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। ये बोलियां ब्रेंट कच्चे तेल के औसत मासिक मूल्य और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की खेप के लिए प्लैट्स वेस्ट इंडिया मार्कर (डब्ल्यूआईएम) के आधार पर मांगी गई हैं। ब्रेंट कच्चे तेल के लिए मौजूदा 117.68 डॉलर प्रति बैरल के मूल्य के हिसाब से न्यूनतम कीमत 19.6 डॉलर प्रति (एमएमबीटीयू) बैठती है। खरीदारों को इसके ऊपर बोली लगानी होगी। वेदांता की सीबी/ओएस-2 ब्लॉक में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऑयल एंड नैचुरल गैस (ओएनजीसी) के पास भी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस ब्लॉक की परिचालक वेदांता एक मई, 2022 से शुरू होकर 14 माह के लिए 2.5 लाख घनमीटर गैस के लिए खरीदार ढूंढ रही है।

तमिल विद्रोह दबाने को लाए गए पीटीए कानून में बदलाव का मानवाधिकार समूहों ने बनाया दबाव

जेनेवा (ईएमएस)। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि श्रीलंका में पीटीए कानून का उपयोग जबरन गिरफ्तारी के लिए होता रहा है। इस कानून के तहत बिना किसी कानूनी कार्रवाई के लोगों को सालों तक हिरासत में रखा जाता है और उन्हें प्रताड़ित करके झूठे काबूलनामें लिखाएं जाते हैं। हालांकि इन आरोपों को श्रीलंका प्राधिकरण खारिज करता रहा है। 40 साल पहले अस्थाई व्यवस्था के तहत यह कानून तब लाया गया जब तमिल राष्ट्र के लिए चल रहा विद्रोह अपने शुरुआती चरण में था।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस कानून का उपयोग अल्पसंख्यक समूहों, सरकार के आलोचकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए किया जाता रहा है। श्रीलंका में सिंहला समुदाय के दबदबे वाली सभी सरकारों ने अलगाववादी संगठन तमिल टाइगर्स (एलटीटीई) से जुड़े संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पीटीए का खूब इस्तेमाल किया। श्रीलंकाई सेना ने 2009 में एलटीटीई के विद्रोहियों को हरा दिया था। श्रीलंका में गृहयुद्ध समाप्त होने के एक दशक बाद यह कानून अभी भी अस्तित्व में है। अब श्रीलंका सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि वह इसमें बदलाव लाए। यूरोप श्रीलंका में बने सामान का एक बड़ा बाजार है, और यूरोप लगातार उस पर मानवाधिकारों के पैमाने पर प्रगति के लिए दबाव डाल रहा है।

श्रीलंकाई जेल प्राधिकरण के अनुसार, पीटीए के तहत अब तक तकरीबन 300 लोग हिरासत में है, जिसमें से कुछ लोग एक दशक से भी ज्यादा समय से जेलों में बंद हैं। सालों तक आलोचना सहने के बाद अब सरकार ने इस कानून में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। न्याय मंत्री मोहम्मद अली साबरी ने कहा कि कानून में सबसे अहम संशोधन जो किया गया है वह यह है कि अगर किसी की कैदी पर 1 साल से ज्यादा समय तक केस शुरू नहीं होता है, तो वह जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि अधिकारी आतंकरोध से जुड़े लंबित मामलों में जल्द निपटने की कोशिश कर रहे हैं और 86 लोगों को हाल ही में रिहा किया गया है।

जिनेवा में आयोजित हो रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है। अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी इसे बेहद करीब से देख रही हैं। यूरोपीय संघ पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर मानवाधिकार के मामलों में प्रगति नहीं होती तो वह श्रीलंकाई कंपनियों के टैरिफ फ्री व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकता है।

रूसी अल्टीमेटम तभी पूरा हो सकता है जब पूरा यूक्रेन नष्ट हो जाए, युद्ध रोकने के लिए बातचीत करें पुतिन : जेलेंस्की

कीव (ईएमएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा युद्ध को खत्म करने का रूस का अल्टीमेटम तभी पूरा हो सकता है, जब पूरा यूक्रेन तबाह हो जाए। जेलेंस्की ने कहा, रूसी कहते हैं कि हमारे पास एक अल्टीमेटम है, शर्ते हैं, इसे पूरा करें फिर हम युद्ध को समाप्त करेंगे। यह गलत है। यह मेरे बारे में नहीं है। यह लोगों की एकता के बारे में है। हम एक साथ ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। यूक्रेन इस अल्टीमेटम को पूरा नहीं कर सकता।

एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम सभी को नष्ट करना होगा, फिर डिफॉल्ट रूप से उनका अल्टीमेटम मिलता है। जेलेंस्की ने उदाहरणों का हवाला दिया जब रूसी सैनिकों ने मेलिटोपोल और बर्डियांस्क के शहरों पर कब्जा कर लिया, लोगों ने उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? हम सभी को नष्ट करना? इसलिए मैंने जवाब दिया कि हम उनका अल्टीमेटम तभी पूरा कर सकते हैं, जब हममें से कोई भी नहीं बचेगा।

एक संभावित युद्धविराम समझौते के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई मांगें रखी हैं, जिसमें यूक्रेन की तटस्थ और गैर-परमाणु स्थिति, विसैन्यीकरण और विमुद्रीकरण, कब्जे वाले क्राइमिया को रूस के रूप में मान्यता और तथाकथित 'डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक' और 'लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक' की संप्रभुता शामिल हैं। इसके जवाब में, जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। इस बीच 17 मार्च को राष्ट्रपति के सलाहकार, मायखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि मांगों की समीक्षा में रूस के साथ कई दिनों की बातचीत हो सकती है, जिसके बाद पुतिन और जेलेंस्की के बीच संभावित बैठक की तैयारी शुरू हो सकती है।

इस बीच जेलेंस्की ने सोमवार देर रात दिए एक अन्य बयान में कहा कि वह संघर्ष-विराम, रूसी सैनिकों की वापसी और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के बदले में नाटो की सदस्यता नहीं लेने के विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं। जेलेंस्की ने कहा यह हर किसी के लिए एक समझौता है। पश्चिम के लिए, जो नहीं जानता कि नाटो के संबंध में हमारे साथ क्या करना है। यूक्रेन के लिए, जो सुरक्षा गारंटी चाहता है और रूस के लिए भी, जो नाटो का विस्तार नहीं चाहता है। जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत के अपने आह्वान को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि जब तक वह पुतिन से नहीं मिलते, यह समझना असंभव है कि क्या रूस भी युद्ध को रोकना चाहता है या नहीं।

कच्चे तेल की ऊंची कीमत के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं : सऊदी अरब

दुबई (ईएमएस)। कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) के बड़े निर्यातकों में शामिल सऊदी अरब ने कहा कि वह यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद उत्पादन प्रभावित होने की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति में कमी की 'कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।' आमतौर पर नपे-तुले बयान देने वाले सऊदी अरब ने असामान्य रूप से कठोर चेतावनी दी है, क्योंकि अधिकारियों को पता है कि उनकी छोटी-छोटी टिप्पणियां भी तेल की कीमत को प्रभावित कर सकती हैं और वैश्विक बाजार में हलचल मचा सकती हैं। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल केंद्रों पर हमले किए हैं, जिससे युद्ध के और तेज होने की आशंका बढ़ गई है, जो 2014 में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा यमन की राजधानी सना और उत्तरी हिस्सों पर कब्जा करने के बाद शुरू हुआ था। सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने हूति विद्रोहियों को हटाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने के लिए भीषण हवाई हमलों के साथ इस कार्रवाई का जवाब दिया। सात साल बाद यह संघर्ष एक खूनी गतिरोध में बदल गया और दुनिया में सबसे बड़े मानवीय संकट में से एक को जन्म दिया। सरकारी 'सऊदी प्रेस एजेंसी' ने सऊदी विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा कि देश 'यह घोषणा करता है कि उसके तेल केंद्रों पर हमलों के मद्देनजर वैश्विक बाजार में अगर तेल की आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी आती है तो वह इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।'

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब उत्पादन सीमित करने वाले सौदे को लेकर ओपेक और अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ सऊदी अरब भी इस तरह की वार्ता कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र के तेल उत्पादकों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच तेल की कीमत घटाने में मदद करने के लिए अधिक कच्चा तेल निकालने के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रस्ताव का अब तक विरोध किया है। सऊदी अरब ने एक बयान में कहा, 'अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सऊदी अरब की तेल उत्पादन क्षमता और उसकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में खलल डालने वाले हमलों को रोकने तथा ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करने में निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।' यमन के ईरान समर्थित विद्रोहियों ने रविवार को सऊदी अरब के तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाकर हमले शुरू किए थे, जिससे देश के दूसरे सबसे बड़े शहर जिद्दा के बंदरगाह में एक पेट्रोलियम वितरण केंद्र में आग लग गई और लाल सागर तट पर यानबू में एक पेट्रोकेमिकल परिसर में उत्पादन बाधित हो गया।

इमरान ने आईओसी में कश्मीर पर जताई हताशा, कहा भारत के खिलाफ एकजुट हों 1.5 अरब मुसलमान

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामिक देशों के संगठन (ओआईसी) के मंच से एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। इस बार खास बात यह रही है कि इस सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद रहे। इमरान खान ने कहा कि हम डेढ़ अरब मुसलमान हैं लेकिन कश्मीर और फलस्तीन का मुद्दा सुलझाने में फेल साबित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि हमारा कश्मीर पर कोई प्रभाव नहीं है, वे हमें गंभीरता से नहीं लेते। कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने अवैध रूप से कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा कि इसकी वजह यह है कि भारत कश्मीर पर कोई दबाव महसूस नहीं करता है। मैं विदेश नीति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हर देश की विदेश नीति अलग-अलग होती है। लेकिन हमें इसके खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत है, नहीं तो ये अत्याचार कश्मीर और फलस्तीन में होते रहेंगे। उधर, बलूचों की आवाज कुचलने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने फलस्तीन की कश्मीर से तुलना करते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि विदेशी हस्तक्षेप के कारण मुस्लिम देशों में आतंकवाद फैल रहा है। कुरैशी ने दावा किया कि कश्मीर और फलस्तीन में मुसलमान मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर में मुस्लिम घिनौने आधिपत्य का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में नरसंहार बहुत निकट है। कुरैशी ने यह भी दावा किया कि भारत कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा, 'इन अवैध कृत्यों की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का खतरा बढ़ गया है।

कुरैशी ने कहा कश्मीरी जनता अपने मुस्लिम भाई और बहनों की तरफ मदद के लिए देख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर में जनसंख्या को बदलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसे मुस्लिम अल्पसंख्यक इलाके में बदल दिया जाए। पाक विदेश मंत्री ने दावा किया कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों खासकर जिनेवा समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों की एकजुटता पाकिस्तान की विदेश नीति के मुख्य आधारों में से एक है।

रूस पर आर्थिक प्रतिबंध, शक्कर के लिए सुपरमार्केट में भिड़ गए लोग, वीडियो वायरल

मॉस्को (ईएमएस)। यूक्रेन पर हमले के कारण आलोचनाओं के झेल रहे रूस पर कई देशों की लगी पाबंदियों की मार रूसी जनता पर पड़ रही है। शक्कर के लिए सुपरमार्केट में रूसी लोगों की आपस में लड़ाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। चीनी की तंगी की वजह से कुछ स्टोर्स ने प्रति ग्राहक 10 किलोग्राम की सीमा लगा दी है। रूस में वार्षिक मुद्रास्फीति 2015 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे चीनी समेत कई खाद्य सामग्रियों की कीमतें आसमान छू रही हैं।

वीडियो में शॉपिंग कार्ट से चीनी के बैग लेने के लिए लोगों की भीड़ को आपस में झगड़ते और धक्का-मुक्की करते देखा जा सकता है। इन वीडियोज को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। ये रूसी-यूक्रेन युद्ध के कारण आम नागरिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर कर रहे हैं। रूसी सरकार के अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि चीनी की कोई कमी नहीं है। यह संकट लोगों की ओर से दुकानों में अधिक खरीदारी करने से पैदा हो रहा है। साथ ही चीनी निर्माताओं की ओर से कीमत बढ़ाने के लिए जमाखोरी की जा रही है। हालांकि, सरकार ने देश से चीनी के निर्यात पर भी अस्थायी रोक लगा दी है। चीनी की कीमत 31 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

पश्चिमी पाबंदियों के कारण दूसरे प्रोडक्ट्स भी महंगे होते जा रहे हैं। कई पश्चिमी स्वामित्व वाले व्यवसायों ने रूस छोड़ दिया है और इसलिए कारों, घरेलू सामानों के साथ-साथ टेलीविजन जैसे विदेशी आयातित सामानों की भारी कमी है। रूसी सरकार ने करेंसी कंट्रोल को लागू करके महंगाई को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है, लेकिन ये बेअसर रहा हैं। पूरे देश में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते आम लोगों का जीवन-यापन मुश्किल हो रहा है।

कारोबार समेट कर जाने वाली कंपनियों की संपत्ति जब्त करेगा रूस, चक्कर में फंसी लीज पर विमान देने वाली कंपनियां

लंदन (ईएमएस)। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के सोमवार को 26 दिन हो गए हैं। अभी भी दोनों देशों के बीच शांति कायम होती नहीं दिख रही है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। कड़े प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे पश्चिमी कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, रूस उन कंपनियों की संपत्तियां जब्त करने का निर्णय लिया है, जो रूस से कारोबार को समेट कर जा रही हैं।

रूस के पास 500 से ज्यादा विमान हैं जो एक विदेश कंपनी से लीज पर लिए गए हैं। इन्हें लीज पर ऑपरेट किया जा रहा है। विमान के लीज पर देने वाली कंपनियों को रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों से 12 से 15 बिलियन डॉलर तक का नुकसान झेलना पड़ जाएगा। आयरलैंड की विमान कंपनी एयरकेप को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस कंपनी के 1000 से भी ज्यादा विमान लगभग 80 देशों में लीज पर चल रहे हैं जिसमें से 150 विमान रूस को लीज पर दिए गए हैं। कंसल्टेंसी फर्म एसीसी एविएशन के आंकड़ों के मुताबिक, इस कंपनी को 2.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं एयरकेप की वेसबाइट के मुताबिक, एरोलोफ्ट, एस7 एयरलाइन, रोसिया, अजुर एयर, युरल एयरलाइंस जैसी रूस की विमान कंपनियां एयरकेप की क्लाइंट हैं। रूस पर यूरोपीय यूनियन के बैन के बाद एयर विमान कंपनी एयरकेप ने रूस की विमान कंपनियों के साथ अपना कांट्रैक्ट भी खत्म करने का ऐलान किया हैं। आयरलैंड की एक अन्य कंपनी एसएमबीसी के भी कई विमान रूस में लीज पर हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि, रूस के पास अभी 980 एयरक्राफ्ट सर्विस में हैं। इनमें से लगभग 777 विमान लीज पर हैं और 515 विमान विदेशी कंपनियों के हैं। वहीं सिंगापुर की कंपनी एओसी एविएशन और आयरलैंड की एक अन्य कंपनी एवलोन के करीब 20-20 विमान रूस में हैं। यह वह कपंनियां है जिनका न केवल लीज समाप्त हो रही है बल्कि आय का भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रूस के खिलाफ कई देशों ने अपना हवाई मार्ग भी बंद कर दिया है।

ट्रैक्टर उद्योग में नए उत्सर्जन मानकों से बदलाव कम होगा

नई दिल्ली (ईएमएस)। ट्रैक्टर उद्योग में नए उत्सर्जन मानकों में बदलाव से क्षेत्र में अधिक उथल-पुथल आने की आशंका नहीं है। इसका कारण यह उन्हीं वाहनों में लागू होगा, जिसका इंजन क्षमता 50 एचपी (अश्व शक्ति) से अधिक है। नई व्यवस्था से उद्योग की कुल 10 प्रतिशत संख्या पर ही असर पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2022 से 50 एचपी से अधिक क्षमता के इंजन वाले ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानक (टीआरईएम 4) लागू होगा। उद्योग का एक बड़ा हिस्सा 50 एचपी से कम क्षमता के इंजन युक्त ट्रैक्टरों का है और इन पर टीआरईएम-3 ए मानक पहले की तरह बने रहेगा। फिलहाल टीआरईएम-तीन-ए उत्सर्जन मानक विभिन्न अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों पर लागू हैं। इस अप्रैल 2010/2011 में लागू किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया हैं कि भारत में लगभग 80 प्रतिशत ट्रैक्टर बिक्री 30-50 एचपी श्रेणियों के अंतर्गत है। संशोधित उत्सर्जन मानदंड केवल 50 एचपी से अधिक ट्रैक्टरों पर लागू होगा। यह कुल उद्योग की मात्रा का लगभग 10 प्रतिशत ही है। उन्होंने कहा कि चूंकि निर्यात मॉडल में इन मानदंडों का अनुपालन पहले से हो रहा है, अतः मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के पास तकनीकी जानकारी पहले से है। नए मानकों से ट्रैक्टरों की कीमतों पर पड़ने वाले असर के बारे में पूछने पर जानकार ने कहा, हमारे अनुमान के अनुसार, इनसे लागत में छह से आठ प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओईएम इसका भार धीरे-धीरे ग्राहकों पर डालेगा। ट्रैक्टरों के लिए संशोधित उत्सर्जन मानदंड पहले अक्टूबर, 2020 से लागू होने थे। हालांकि, इस शुरू में एक साल के लिए और बाद में कोरोनो महामारी के मद्देनजर छह महीने के लिए टाल दिया गया था।

एलन मस्क ने मंगल ग्रह पर पहुंचने की तारीख फिर बदली

-मस्क का सपना मंगल पर कदम रखने का नहीं बल्कि 'लाल ग्रह' पर इंसानों की पूरी कॉलोनी बसाने का है

वॉशिंगटन (ईएमएस)। खगोलीय वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों में जीवन की तलाश में सतत प्रयत्नशील है। कई साल पहले ही चांद पर कदम रख चुके हैं और अब मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क का सपना सिर्फ मंगल पर कदम रखने का नहीं बल्कि 'लाल ग्रह' पर इंसानों की पूरी कॉलोनी बसाने का है।

एलन मस्क ने दावा किया था कि 2024 में मानव मंगल ग्रह पर कदम रखेगा लेकिन अब उन्होंने अपनी इस तारीख को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। एलन मस्क ने 2016 में मंगल ग्रह पर इंसानों का शहर बसाने का अपना प्लान दुनिया के सामने रखा था। उस वक्त मस्क ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 2024 तक एक क्रू मिशन मंगल ग्रह पर कदम रख सकता है। इसके बाद मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने मंगल ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट निर्माण के कई प्रयास किए लेकिन लग नहीं रहा कि मस्क की डेटलाइन तक यह काम पूरा हो पाएगा। खुद मस्क ने बुधवार को ट्विटर पर एक यूजर को जवाब देते हुए इसका खुलासा किया।

एलन मस्क के अनुसार इंसान कम से कम 2029 तक मंगल पर कदम रख पाएगा, यानी 1969 में चांद पर पहली बार इंसान के पहुंचने के 60 साल बाद। मस्क ने दूसरी बार इंसान के मंगल पर पहुंचने की तारीख बदली है। दिसंबर 2020 तक उन्होंने इसके लिए 2026 का लक्ष्य रखा था। स्पेसएक्स नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चांद और भविष्य में मंगल पर भेजने के लिए 'स्टारशिप' को डिजाइन कर रहा है। स्टारशिप ने कई ऊंची उड़ानें तो भरी हैं लेकिन अभी तक यह अंतरिक्ष में जाने में कामयाब नहीं रहा है। एलन मस्क के बाद दुनिया के कई अमीर उद्योगपति अंतरिक्ष में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। हालांकि इन्होंने स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में कदम रखा है और आम यात्रियों को 'अंतरिक्ष की सीमा' तक भेजा है। लेकिन एलन मस्क का इरादा सिर्फ अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचना नहीं है। वह स्पेस स्टेशन और उसके आगे मंगल तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं।

अमेरिकी मेडिकल एक्सपर्ट की चेतावनी, बूस्टर शॉट या चौथी डोज की जरूरत पड़ेगी

वॉशिंगटन (ईएमएस)। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी का यह तीसरा साल है। कई देशों में फिर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना के ओमिक्रॉन बीए.2 वेरिएंट से इंफेक्शन के ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। इसतरह के हालात में कोरोना ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी टॉप मेडिकल एक्सपर्ट डॉ. एंथनी फौसी ने चेतावनी दी है कि यूएस में आने वाले हफ्तों में कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोविड की सेकंड बूस्टर शॉट या चौथी डोज की जरूरत भी पड़ सकती है।

दवा निर्माता कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना कोरोना-रोधी चौथी डोज लेकर तैयार है। इन कंपनियों ने अमेरिकी प्रशासन से चौथी डोज के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार फौसी ने यूरोप में मामलों में वृद्धि का हवाला दिया। उन्होंने कहा,बीए.2 वेरिएंट ओमिक्रॉन की तुलना में लगभग 50 से 60 प्रतिशत या उससे अधिक संक्रामक है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में यह डोमिनेंट वेरिएंट हो सकता है। डर इस बात का है कि यूरोप में जिस तेजी से कोरोना केस बढ़ थे, उसी तेजी से इस वेरिएंट के चलते फिर से मामले सामने आ सकते हैं।ठ

वहीं, डब्ल्यूएचओ की कोरोना तकनीकी प्रमुख मारिया वेन केरकोव ने कहा कि महामारी खत्म हो चुकी है, ओमिक्रॉन हल्का है, यह कोविड का आखिरी वेरिएंट है, जैसी कई गलत जानकारियां दुविधा पैदा कर रही हैं। केरकोव ने कहा कि बीए.2 अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट दिख रहा है। उन्होंने जानकारी दी, हमें आबादी के स्तर पर बीए.1 से तुलना में बीए.2 की गंभीरता में कोई बदलाव नजर नहीं आया। हालांकि, ज्यादा मामलों के साथ आप अस्पतालों में भर्ती होने की संख्या में इजाफा देख सकते हैं, और यह बढ़ी हुई मौतों में बदल जाता है।'

इन दिनों इटली में कोरोना केस तेज से बढ़ रहे हैं। यहां रविवार को 60,415 कोविड केस मिले। एक दिन पहले ही इटली में 74,024 मामले सामने आए थे। यूनाइटेड किंगडम में भी डेली केसों में वृद्धि देखी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, यूके में 14 मार्च को 170,000 मामले दर्ज किए गए थे। दरअसल, देश ने ईस्टर समारोह के लिए कोविड प्रतिबंध हटा लिया था। वहीं, चीन ने दो साल में सबसे बड़े प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। शंघाई शहर में डिज्नी थीम पार्क को बंद कर दिया गया है। यह शहर 2020 के बाद से अपने सबसे खराब प्रकोप से जूझ रहा है।

कृषि क्षेत्र हमारे लिए प्राथमिकता था, है और रहेगा: मुख्यमंत्री

- भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में 172वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक संपन्न, वित्त मंत्री भी रहे मौजूद

अहमदाबाद (ईएमएस)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साफ किया कि कृषि क्षेत्र हमारे लिए प्राथमिकता था, है और रहेगा। इस उद्देश्य से यह आवश्यक है कि बैंकिंग सेक्टर कृषि, पशुपालन और मत्स्योद्योग जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा बजट में ऋण वितरण के लिए किए गए प्रावधानों का व्यापक लाभ लाभार्थियों को मुहैया कराने के लिए सक्रियता के साथ पहल करे। यह बात उन्होंने मंगलवार को गांधीनगर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 172वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि शून्य फीसदी ब्याज दर पर ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालन और मत्स्योद्योग क्षेत्र में देने के जो प्रावधान इस वर्ष बजट में किए गए हैं, उसका लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकों को अपना तंत्र विकसित करना होगा। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, मुख्य सचिव पंकज कुमार, एसएलबीसी के चेयरमैन विक्रमादित्य खिची, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक राजेश कुमार, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश पुरी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव जेपी गुप्ता और वरिष्ठ सचिवों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों ने इस बैठक में शिरकत की।

बतौर मुख्यमंत्री पदभार संभालने के बाद पहली बार एसएलबीसी की बैठक को संबोधित करते हुए भूपेंद्र पटेल ने सामान्यतम व्यक्ति और हाशिये के ग्रामीण नागरिकों को भी स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सेवाएं सुलभ कराने के लिए बैंकिंग सेवाओं के डिजिटाइजेशन के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ठेले-खोमचे वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना और स्वामित्व योजना सहित कमजोर वर्ग के कल्याण की योजनाओं के अंतर्गत ऋण सहायता देने के लिए जल्द ही आवश्यक कार्यवाही शुरू करे। पटेल ने कहा कि देश को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प बैंकिंग सेक्टर और राज्य सरकार दोनों की सक्रिय सहभागिता से 'आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत' के सूत्र द्वारा साकार होगा।

वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण गरीब हितैषी रहा है, तब आम लोगों और जरूरतमंद लाभार्थियों को बैंक से ऋण प्रदान करने के मामले में बैंकों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे आम लोगों के ऋण आवेदनों को मामूली वजहों से लंबित रखने या रद्द करने के बजाय यह आवश्यक है कि बैंकर्स उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।

मुख्य सचिव पंकज कुमार ने बैंकर्स से मिशन मोड में कार्यरत होने का आह्वान करते हुए कहा कि एसएलबीसी की यह 172वीं बैठक है यानी पिछले 42-43 साल से ऐसी बैठकें आयोजित हो रही हैं। अब हमें घिसी-पिटी कार्यप्रणाली से बाहर निकलकर ऐसे नवीनतम दृष्टिकोण से विचार करने की जरूरत है। पंकज कुमार ने इस संबंध में आगे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गरीब और किसान उन्मुख, ग्रामीण विकास, नल से जल और स्वामित्व सहित सभी योजनाओं में संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ कार्यपद्धति का रवैया अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के सभी विभाग इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। ऐसे में बैंकों को भी सक्रिय दृष्टिकोण और उनके पास मौजूद सभी डेटाबेस के आधार पर प्रत्येक योजनाओं का विश्लेषण कर लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है।

एसएलबीसी के चेयरमैन श्री विक्रमादित्य खिची ने राज्य में बैंकिंग सेक्टर और राज्य सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय के चलते जारी कार्यों पर प्रकाश डालते कहा कि राज्य में पांच किलोमीटर की त्रिज्या में नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, 9800 से अधिक बैंक शाखाओं और 12 हजार से अधिक एटीएम की सेवाएं भी आसानी से मिल रही है। खिची ने उम्मीद जताई कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत 14,800 से अधिक गांवों में लाभार्थियों के सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान से योजना को लागू करने में बैंकों को आसानी रहेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार के विभाग और अधिकारियों के सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप बैंकर्स को विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने में प्रोत्साहन मिलता है, जो प्रशंसनीय है।

बैठक के दौरान दिए गए प्रेजेंटेशन के अनुसार गुजरात में प्रायोरिटी सेक्टर यानी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण सहायता के मामले में दिसंबर, 2021 तक 82.89 फीसदी की उपलब्धि हासिल की गई है।

कांग्रेस के 3 नेताओं को कोर्ट का समन, पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप

अहमदाबाद (ईएमएस)। गांधीनगर की अदालत ने कांग्रेस के 3 नेताओं के खिलाफ समन जारी कर जवाब तलब किया हैं। कांग्रेस के इन तीन नेताओं ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर जमीन के मामले में 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। विजय रूपाणी ने कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का दावा किया हैं। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा, उप नेता शैलेष परमार और कांग्रेस के दंडक सीजे चावडा ने आरोप लगाया था कि राजकोट के निकट स्थित नवागाम आणंदपर गांव की जमीन मामले में रु. 500 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में बाकायदा पत्रकार परिषद कर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अलावा नितिन भारद्वाज समेत भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस संदर्भ में नितिन भारद्वाज ने राजकोट पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत देकर कहा था कि हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे और पोलिटिकल कैरियर खत्म करने के लिए हैं। झूठे आरोप करनेवाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने की नितिन भारद्वाज ने मांग की थी। अगर 10 दिन के भीतर कांग्रेस नेता माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगें। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अमेरिका प्रवास से लौटने के बाद विपक्ष के नेता सुखराम राठवा, उप नेता शैलेष परमार और कांग्रेस के दंडक सीजे चावडा को एडवोकेट अंश भारद्वाज के जरिए मानहानि करने के लिए नोटिस जारी की गई थी। गत 2 मार्च को कोर्ट में दाखिल याचिका में सुखराम राठवा, शैलेष परमार और सीजे चावडा के खिलाफ दफा 202 के तहत कार्यवाही करने की मांग की गई। इस संदर्भ में कोर्ट ने शिकायतकर्ता विजय रूपाणी के वकील की दलीलें और प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए सुखराम राठवा, शैलेष परमार और सीजे चावडा के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 115 के अंतर्गत कार्यवाही करने और क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की धारा 204 के तहत फौजदारी केस दर्ज कर समन जारी किया हैं।

गुजरात सरकार सभी लोगों के 'अपने का घर' सपने को साकार करने हेतु कटिबद्ध : मुख्यमंत्री

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हर नागरिक को 'घर का घर' मिले इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देखे गए सपनें को साकार करने हेतु गुजरात सरकार कटिबद्ध है और इस दिशा में परिणामोन्मुखी कदम उठाए है। उन्होंने अहमदाबाद पूर्व के ओढव स्थित इंदिरानगर में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागरिकों को 271 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भेंट दी। इस असवर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अहमदाबाद शहर की झुग्गियों में रहने वाले ग़रीबों को पक्के आवास मुहैया कराने की योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 179 करोड़ रुपए के हाउसिंग परियोजना, 47 करोड़ रुपए की जलापूर्ति परियोजना तथा 1 करोड़ रुपए की हेरिटेज परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि है कि सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण की गई परियोजनाओं के अंतर्गत 1610 आवास और 52 दुकानें नागरिकों को समर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने आवासों का उचित रख-रखाव करने का अनुरोध करते हुए कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान यह सामान्य मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है और इन्हें पूरी करने हेतु गुजरात सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ग़रीब तथा मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं को लेकर कई योजनाएँ बना रही हैं। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विशेषकर ग़रीब, मध्यम वर्ग के लोगों का सपना होता है कि शहर में उसका खुद का 'घर का घर' हो तथा उनके सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने परिणामन्मोखी प्रयास किए हैं। ग़रीबों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के मुश्किल समय में कोई ग़रीब भूखा न सो जाए इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चिंता करते हुए ग़रीबों को निःशुल्क अनाज दिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार सामान्य नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। इतना ही नहीं गुजरात के नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 10 करोड़ से अधिक डोज़ दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शहर के लोगों का मिलनसार स्वाभाव और अनुकूल दृष्टिकोण के चलते सर्वांगीण विकास हो रहा है। लोगों की इन्हीं विशेषताओं के कारण ही शहर में व्यापार-रोज़गार का विकास हुआ है।

इस अवसर पर राज्य के उद्योग मंत्री जगदीश पंचाल ने कहा कि भूतकाल में सरकारें सिर्फ वादें किया करती थी, किन्तु नरेन्द्र मोदी ने सभी परिवार को घर देने का संकल्प लिया और आज यह सच हो रहा है। शहरी विकास राज्य मंत्री श्री विनोद मोरडिया ने अपने प्रासंगिक संबोधन में कहा कि आज अनेक लाभार्थियों को जो लाभ मिल रहा है, वही लाभ भविष्य में भी अन्य लाभार्थियों को भी दिया जाएगा। उन्होंने राज्य के प्रत्येक परिवार को आवास मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

धुलेटी पर विद्यार्थिनी के साथ चार विद्यार्थियों ने छेड़छाड़ किया

अहमदाबाद, २२ मार्च ।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एमए के प्रथम वर्ष में पढ़ाई करती एक विद्यार्थिनी ने चार अन्य विद्यार्थियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है । विद्यार्थिनी की शिकायत के अनुसार गुरुवार को कैंपस में धुलेटी के उत्सव के दौरान यह चार विद्यार्थियों ने इसके साथ छेड़छाड़ किया । शिकायत मिलने के बाद यूनिवर्सिटी की इंटरनल कम्पलेइन कमेटी ने यह घटना की जांच शुरू कर दी है । सीयूजी के इंचार्ज रजिस्ट्रार संजय झा ने शिकायत मिली होने की बात की पुष्टि की है । उन्होंने बताया है कि, कॉलेज प्रशासन को एक विद्यार्थिनी की शिकायत मिली है, जिसे ध्यान में रखकर आईसीसी के सदस्यों ने सोमवार को एक मीटिंग रखी थी । उल्लेखनीय है कि गुजरात के गांधीनगर के सेक्टर २९ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात स्थित है । यूनिवर्सिटी के सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, जिस विद्यार्थिनी ने शिकायत दर्ज कराई है वह दक्षिण भारत की है । विद्यार्थियों ने जब पानी से होली खेलने की शुरूआत की तब वह कैंपस में थी । यूनिवर्सिटी के एक सूत्र ने बताया कि, होली खेलते कुछ विद्यार्थियों ने इसे भी जश्न में शामिल होने को कहा था लेकिन उसने मना कर दिया । इसके बाद एमए के दूसरे वर्ष में जर्मन का पढ़ाई करता एक विद्यार्थी उसे खींचकर लाया था । उसने शोर मचाया फिर भी उसने अन्य विद्यार्थियों को भी भड़काया और इस पर पानी डाल दिया । सूत्र ने आगे बताया है कि, अन्य तीन विद्यार्थियों ने भी इसे उठाकर और रंगीन पानी और कीचड़ के गड्ढे में फेंक दिया । यह लोगों ने जबरदस्ती इस पर रंग डाल दिया और कथित रूप से इसके साथ छेड़छाड़ किया । यह सभी घटना से डर गई विद्यार्थिनी रोने लगी थी और मदद मांग रही थी । उसने सिक्योरिटी गार्ड की भी मदद मांगी जिन्होंने यह चार विद्यार्थी ने कैंपस छोड़कर भाग नहीं जाए इसके लिए दरवाजा बंद कर दिया था ।

स्पा की आड में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने रेड कर महिला समेत तीन लोगों को पकड़ा

सूरत (ईएमएस) शहर के वराछा क्षेत्र के मारुति चौक में स्पा की आड में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने रेड कर महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया हैं। पकड़ी गई महिला ग्राहकों से 800 रुपए लेकर युवतियों को केवल 300 रुपए देती थी। जानकारी के मुताबिक सूरत के वराछा क्षेत्र के मारुति चौक के निकट प्लोट नंबर 117 की पहली मंझिल पर 30 वर्षीय भारती रामचंद्र स्वाई नामक महिला स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाती थी। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर सूरत के वराछा पुलिस ने गत शाम अनमोल स्पा में रेड कर चार युवतियों और चार ग्राहकों को दबोच लिया। पुलिस की छापेमारी के दौरान तीन युवतियां और तीन ग्राहक आपत्तिजनक स्थिति पकड़े गए। स्पा की आड में सेक्स रैकेट चलानेवाली 30 वर्षीय भारती रामचंद्र स्वाई ग्राहकों से रु. 800 वसूलती और युवतियों को केवल रु. 300 देती थी। भारती स्वाई 35 वर्षीय रतिकांत हरिकृष्णा जैना के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चलाती थी। पुलिस ने घटनास्थल से रु. 17450 नकद, रु. 52 हजार कीमत के 7 मोबाइल फोन, 8 कोन्डोम समेत कुल रु. 67450 का माल सामान जब्त कर लिया। वराछा पुलिस ने भारती स्वाई, रतिकांत जैना और किराए पर दुकान देनेवाले मनोज नागजी मावाणी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की।

पोपटभाई फतेपरा ने पत्र लिखा

नरेश पटेल को लेकर पाटीदार समाज में विरोध किया गया

पत्र में बताया है कि नरेश पटेल खोडलधाम को राजनीतिक अखाडा बना रहे है उमियाधाम में प्रवेश नहीं देना

राजकोट, २२ मार्च ।

वींछिया के सनाली गांव के निवासी और जसदण-वींछिया क्षेत्र के कडवा पटेल समाज के सीनियर पोपटभाई फतेपरा ने ऊंझा, सिदसर और गांठीला उमियाधाम के प्रमुख को एक पत्र लिखा है । जिसमें उन्होंने बताया है कि, दोहरी नीतिवाला खोडलधाम के नरेश पटेल को यह तीनों मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाए । पटेल समाज के सीनियरों ने एक मंच पर आने से और पाटीदार समाज की एकता से भारतीय जनता पार्टी ने पाटीदार समाज के १ मुख्यमंत्री और ७ मंत्रियों को गुजरात सरकार में स्थान दिया है । लेकिन मुख्यमंत्री कडवा पाटीदार समाज के होने की वजह से नरेश पटेल निवेदन करते है कि लेउवा पटेल समाज के विधायकों को मुख्य खाते आवंटित नहीं कराया गया है । पत्र में बताया गया है कि, एक तरफ कडवा और लेउवा पटेल समाज की मीटिंग में सीनियरों की मौजूदगी में नरेश पटेल यह कहते है कि, अब से कडवा और लेउवा नहीं लेकिन पाटीदार समाज के है ऐसी बातें करते है और पीछे से नरेश पटेल यह कहते है कि लेउवा पटेल समाज को मंत्रिमंडल में मुख्य खाता आवंटित नहीं कराया है । यदि अभी लेउवा और कडवा का विवाद पैदा करना हो तो नरेश पटेल ने पाटीदार समाज नहीं लेउवा पाटीदार समाज बोलना पड़ेगा और पाटीदार समाज की एकता भूल जानी पड़ेगी । जहां तक नरेश पटेल में पाटीदारवाद और राष्ट्रवाद नहीं पैदा होगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा । पत्र में आगे बताया गया है कि, कडवा पटेल समाज की उमिया माताजी की संस्था ऊंझा, सिदसर और गांठीला की संस्थाओं में कभी भी राजनीति को किसी दिन स्थान नहीं दिया गया है, जबकि नरेश पटेल खुलेआम खोडलधाम कागवड को राजनीतिक अखाडा बनाने तरफ जा रहे है । नरेश पटेल कडवा पटेलों को हलाहल नफरत करते है ऐसे कई उदाहरण पहले के वर्षों में सौराष्ट्र में देखने को मिला है । आगे बताया है कि, सिदसर, ऊंझा, गांठिला और खोडलधाम मंदिर के सीनियरों की मीटिंग में पाटीदार समाज की एकता बताने की बातें करके नरेश पटेल लेउवा पटेल समाज के अन्याय मामले में बोलते रहते है ।

राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, खेल महाकुंभ के लिए फिर शुरू किया रजिस्ट्रेशन

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात सरकार ने खेल महाकुंभ को लेकर अहम फैसला किया है, इसके अंतर्गत आज से दो दिनों के लिए खास मामलों में रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू किया गया हैं। खेल मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि राज्य के युवा खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता हैं। खेल महाकुंभ की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष होनेवाले खेल महाकुंभ के लिए करीब 55 लाख से भी अधिक खिलाडियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हैं। हर्ष संघवी ने बताया कि इस वर्ष खेल महाकुंभ के लिए कुछ खिलाडियों की मांग को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने युवाओं के हित में महत्वपूर्ण फैसला किया हैं। इसके अंतर्गत मंगलवार की सुबह 10 बजे से बुधवार की सुबह 11.59 बजे तक खास मामलों में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हर्ष संघवी ने खेलों के प्रति रुचि रखने वाले खिलाडियों से इस अवसर का उपयोग करने की अपील की हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह २६ मार्च को राज्य के दौरे पर

गांधीनगर, २२ मार्च ।

विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है वैसे ही राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है । एक के बाद एक केंद्रीय नेता गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं । केंद्रीय गृहमंत्री और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अमित शाह भी २६ मार्च को गुजरात राज्य के दौरे पर आ रहे है । अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भाजपा के नेताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा । अमित शाह कलोल और अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न लोकार्पण करेंगे इसके अलावा जनसभा को संबोधित कर सकते है । अमित शाह कलोल में १ करोड़ के खर्च से तैयार होने वाला सरदार बाग के रिडेवलपमेंट प्रॉजेक्ट के विशेष मुहूर्त और १८ करोड़ के खर्च से तैयार होने वाला रेलवे पूर्व ब्रिज के विशेष मुहूर्त कार्यक्रम में उपस्थित होंगे । अमित शाह कलोल तहसील में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे । इसके साथ ही गांधीनगर जिले को श्रेष्ठ जिला बनाने के लिए और ग्राम विकास के लिए सरपंचों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते है । उल्लेखनीय है कि, विधानसभा चुनाव निकट आ रहा है तब मतदाताओं के मत लेने के लिए संबंधित मुद्दे पर भी ध्यान देने के लिए तैयारियां होने की संभावना है । हाल यह दौरा २०२२ विधानसभा चुनाव के लिए कलोल तहसील के लिए महत्व की साबित हो सकती है । विधानसभा चुनाव के तहत बैठकें करे ऐसी संभावना रही है ।

एसटी निगम को होली के त्यौहार पर लाभ हुआ, ३.७६ करोड़ की आय

दो वर्ष के बाद होली का त्यौहार और डाकोर का मेला हुआ जिसकी वजह से यात्रियों की भीड़ भी ज्यादा रही

अहमदाबाद, २२ मार्च ।

एसटी निगम को होली के त्यौहार पर लाभ हुआ है । एसटी निगम द्वारा होली के त्यौहार को लेकर अतिरिक्त ९०० से ज्यादा बस चलाई गई थी । दो वर्ष के बाद होली का त्यौहार और डाकोर का मेला हुआ । जिसकी वजह से यात्रियों की भीड़ भी ज्यादा रही । एसटी निगम द्वारा १३ से १८ मार्च के होली के त्यौहार के लिए अतिरिक्त एसटी बस चलाई गई थी । जिसमें एसटी निगम ६९३२ ट्रीप का संचालन किया था । जिसमें ३.१९ लाख यात्रियों ने यात्रा की थी । जिसकी वजह से एसटी निगम को ३.७६ करोड़ की आय हुई है । एसटी निगम के सचिव केडी देसाई ने बताया है कि, डाकोर के मेला एक तरफ का ट्रैफिक मिलता है । क्योंकि भक्त फागणी पूर्णिमा करने के लिए चलकर जाते है और आते है तब बस में आते है । यानी कि डाकोर से बस की सुविधा मिले इसके लिए विशेष आयोजन किया गया था इसके साथ पंचमहाल तरफ का ज्यादा ट्रैफिक मिलता है और यात्रियों को सुविधा मिलती रहे इसके लिए अतिरिक्त एसटी बस चलाई गई थी । जिसमें एसटी बस में ६ दिन में ३.१९ लाख लोगों ने यात्रा की और यात्रियों को सुरक्षित घर पर पहुंचाने का काम एसटी निगम ने किया है । एसटी निगम को सबसे ज्यादा आय अंबाजी पूर्णिमा का मेला और डाकोर के मेले की वजह से होती है । लेकिन पिछले दो वर्ष से कोरोना की वजह से मेला बंद था । यह त्यौहारों में भी छूट नहीं मिलती थी जिसकी वजह से दो वर्ष से त्यौहारों में विशेष आयोजन नहीं किया गया था तथा एसटी निगम को भी कोरोना की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ था । लेकिन परिस्थिति सामान्य होने पर गाड़ी पटरी पर चढ़ रही है । कोरोना केस कम होने पर केपेसिटी भी बढ़ा दी गई है इसके साथ डाकोर के मेले की वजह से आय में वृद्धि हुई है । दो वर्ष के बाद लोग अपने परिवार और रिश्तेदार संबंधित के साथ त्यौहार मनाने के लिए बाहर निकले है ।

पुणे एवं जयपुर (वाया वसई रोड) के बीच एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की सुविधा तथा उनकी मांग को पूरा करने के लिए एक साप्ताहिक एसी सुपरफास्ट विशेष ट्रेन पुणे और जयपुर के बीच वाया वसई रोड चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 01401/02 पुणे-जयपुर-पुणे एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल (20 फेरे)

ट्रेन संख्या 01401 पुणे-जयपुर एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल 12 अप्रैल, 2022 से 14 जून, 2022 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यह ट्रेन पुणे से 00.30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 23.10 बजे जयपुर पहुंचेंगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 01402 जयपुर-पुणे एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल 13 अप्रैल, 2022 से 15 जून, 2022 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। यह ट्रेन जयपुर से 00.35 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 23.35 बजे पुणे पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में लोनावाला, कल्याण, वसई रोड, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, मंदसोर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़ और फुलेरा स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 3 टियर कोच हैं। उक्त ट्रेन विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी।

ट्रेनों के ठहराव और संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों को बोर्डिंग, यात्रा और गंतव्य के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों तथा एसओपी का पालन करने का अनुरोध किया गया है।

ओखा-गुवाहाटी और ओखा-वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेनें छायापुरी स्टेशन से होकर चलेगी

राजकोट (ईएमएस) राजकोट रेल मंडल की दो जोड़ी ट्रेनें वडोदरा की बजाय छायापुरी होकर चलेंगी। उक्त दिनांक से ये ट्रेनें वडोदरा नहीं जाएगी। इससे वडोदरा स्टेशन पर इंजन के रिवर्सल और कंजेशन में लगने वाले समय की बचत होगी। राजकोट डिविजन के सीनियर डीसीएम अभिनव जेफ के अनुसार इन ट्रेनों के कुछ स्टेशनों के आगमन- प्रस्थान के समय में परिवर्तन किया गया है जो निम्नानुसार रहेगा :-

1. ट्रेन संख्या 15635 ओखा-गुवाहाटी सप्ताहिक एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 15635 ओखा-गुवाहाटी सप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 25 मार्च, 2022 से विरमगाम स्टेशन पर 20:00 बजे, अहमदाबाद 21:25 बजे, नडियाद 22:29 बजे तथा 23:30 बजे छायापुरी स्टेशन पर पहुंचकर गुवाहाटी के लिए प्रस्थान करेगी।

2. ट्रेन संख्या 22969 ओखा-वाराणसी साप्ताहिक एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 22969 ओखा-वाराणसी साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 24 मार्च, 2022 से आणंद स्टेशन पर 00:30 बजे तथा छायापुरी स्टेशन पर 01:07 बजे पहुंचकर वाराणसी के लिए प्रस्थान करेगी।

3. ट्रेन संख्या 15636 गुवाहाटी-ओखा साप्ताहिक एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 15636 गुवाहाटी-ओखा साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 28 मार्च, 2022 से छायापुरी स्टेशन पर 11:35 बजे, नडियाद 12:26 बजे तथा 13:50 बजे अहमदाबाद पहुंचकर ओखा के लिए प्रस्थान करेगी। अहमदाबाद तथा ओखा के बीच इस ट्रेन के ठहराव एवं समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

4. ट्रेन संख्या 22970 वाराणसी-ओखा एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 22970 वाराणसी-ओखा एक्सप्रेस छायापुरी स्टेशन पर दिनांक 26 मार्च, 2022 से 19:56 बजे, आणंद 20:41 बजे तथा 22:20 बजे अहमदाबाद पहुंचकर ओखा के लिए प्रस्थान करेगी। अहमदाबाद तथा ओखा के बीच इस ट्रेन के ठहराव एवं समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

गुजरात के 29 जिले और 3 महानगरों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं

अहमदाबाद (ईएमएस)। मंगलवार को गुजरात में कोरोना के 10 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 27 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए। राज्य में रिकवरी रेट 99.08 प्रतिशत हैं। इस दौरान एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। दूसरी ओर राज्य के 29 जिले और 3 महानगरों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। मंगलवार को 2.60 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में 6, वडोदरा कॉर्पोरेशन में 2, सूरत कॉर्पोरेशन में 1 और वडोदरा में 1 समेत राज्यभर में कोरोना के केवल 10 नए मरीज सामने आए हैं। जबकि 27 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में अब तक 1212540 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10942 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 5 महानगर और 32 जिलों में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। वहीं 29 जिले और 3 महानगरों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। राज्य में फिलहाल 308 एक्टिव केसों में 304 स्टेबल हैं और 4 मरीज वेन्टीलेटर पर हैं। दूसरी ओर टीकाकरण अभियान के तहत आज 2640440 नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया हैं। जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के 2616 को पहला और 21616 लोगों को कोरोना का दूसरा डोज दिया गया। 15 से 18 वर्षीय 2451 किशोरों को पहली और 10931 को कोविड की दूसरी वैक्सीन लगाई गई। 12 से 15 वर्षीय 206879 किशोरों को कोरोना पहला टीका लगाया गया। जबकि 15947 नागरिकों को प्रीकॉशन डोज दिया गया। राज्य में अब तक 105154419 नागरिकों को वैक्सीनेट किया जा चुका हैं।

कलर्स शो 'स्पाई बहू' के सना सैय्यद और सेहबान अजीम अहमदाबाद पहुंचे

स्पाई बहू का प्रीमियर 14 मार्च 2022 को हुआ था और अब इसका प्रसारण हर सोमवार-शुक्रवार रात 9:00 बजे केवल कलर्स पर हो रहा है।

अहमदाबाद, 22 मार्च 2022: प्यार एक खूबसूरत एहसास है, और कहा जाता है कि आप इसे सबसे असामान्य जगहों पर पाते हैं। इसमें आपके दिल पर जादू करने और आपको एक और खूबसूरत और रोमांटिक दुनिया में ले जाने की शक्ति है। लेकिन जब दो लोगों के बीच प्रेम की नींव एक धोखे के रूप में रखी गई हो तब क्या होगा? यह कहानी रहस्यपूर्ण हो जाती है। एक शानदार प्रेम कहानी की शुरुआत करते हुए कलर्स ने एक अनोखा रोमांटिक ड्रामा 'स्पाई बहू' लॉन्च किया। जामनगर, गुजरात के खूबसूरत शहर में सेट, यह शो एक जासूस सेजल (सना सैय्यद द्वारा अभिनीत) की यात्रा का अनुसरण करता है, जो एक संदिग्ध आतंकवादी योहान नंदा (सेहबान अजीम द्वारा अभिनीत) को पकड़ने के लिए एक मिशन पर निकलती है, लेकिन अंत में उसके साथ प्यार में पड़ जाती है। किसी भी अन्य जोड़े की तरह सेजल और योहान एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही वह एक दूसरे से कुछ रहस्य छुपा रहे हैं और अपना रिश्ता बिगाड़ने का जोखिम भी उठा रहे हैं।

अपनी नई यात्रा पर निकलते हुए शो के मुख्य किरदार सहबान अजीम और सना सैयद अहमदाबाद शहर पहुंचे। शहर के अंदर लोगों से बात करते हुए इन दोनों अभिनेताओं ने शो के आगामी कथानक और उनके संबंधित पात्रों के बारे में विस्तार से बात की। दोनों अभिनेताओं ने शहर के कुछ जाने-माने स्थानों का दौरा भी किया।

टाटा मोटर्स 1 अप्रैल 2022 से अपने वाणिज्यिक वाहनों के दाम बढ़ाएगा

मुंबई, 22 मार्च, 2022: भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने अपनी वाणिज्यिक वाहन श्रृंखला के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। इस श्रृंखला के मूल्ये में बढ़त की सीमा 2-2.5ङ तक होगी और 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। मूल्यढ में बढ़त की सीमा का अंतर मॉडल और वैरियेंट पर निर्भर होगा।

स्टीयल, एल्यु मिनियम और अन्यय मूल्यिवान धातुओं जैसी कमोडिटीज के दाम बढ़ने और अन्या कच्चेर माल के दामों में तेजी के कारण वाणिज्यिक वाहनों का मूल्य् बढ़ाया जा रहा है। कंपनी ने बढ़े हुए दामों को अपने तक रखने के लिये विनिर्माण के विभिन्नण स्त रों पर कदम उठाये हैं, लेकिन कुल इनपुट की लागत तेजी से बढ़ने के कारण उसका कुछ भाग दामों में न्यूकनतम बढ़त से लेना जरूरी था।

रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) 24 मार्च को खुलेगा

अहमदाबादः पतंजलि ग्रुप के एक अंग रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर के लिए 615 से 650 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ठकंपनीठ या ठरुचि सोया'') का फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और सोमवार, 28 मार्च, 2022 को बंद होगा।

कंपनी एक विविधीकृत एफएमसीजी और एफएमएचजी केंद्रित कंपनी है, जिसके पास रणनीतिक रूप से स्थित विनिर्माण इकाइयां और अखिल भारतीय मौजूदगी वाले प्रतिष्ठित ब्रांड मौजूद हैं।

कंपनी ने इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजरों की सलाह से सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुरूप एंकर निवेशकों की भागीदारी पर विचार किया, जिनकी भागीदारी बिड/इश्यू खुलने की तिथि से एक कार्यदिवस पहले यानी बुधवार, 23 मार्च, 2022 होगी।

कंपनी ने 'पतंजलि' के बिस्किट, कुकीज, रस्क, नूडल्स और ब्रेकफास्ट सीरील्स वाले उत्पाद पोर्टफोलियो का अधिग्रहण करके अपने पैकेज्ड फूड पोर्टफोलियो का विस्तार किया है और पतंजलि ग्रुप का अंग बन चुकी है, जो भारत की अग्रणी एफएमसीजी और हेल्थ एवं वेलनेस कंपनी है। न्यूट्रास्युटिकल और वेलनेस उत्पादों में पतंजलि ग्रुप के 14 वर्षों के अनुभव की बदौलत रुचि सोया ने 'पतंजलि और न्यूट्रीला' की संयुक्त ब्रांडिंग के तहत अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स लॉन्च किए हैं।

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इश्यू (बीआरएलएम) के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

पश्चिम रेलवे

उधना स्टेशन का पुनर्विकास

उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे, सूरत द्वारा निम्नलिखित निविदा हेतु ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in के जरिये प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं. निविदा क्र. डीवाई.सीई(सी) एसटी/ईपीसी/01 दिनांक : 10.03.2022. कार्य का नाम : पश्चिम रेलवे में मुंबई मंडल के उधना में उधना स्टेशन का पुनर्विकास. एनआईटी मूल्य : ₹ 211,92,97,546/-, ईएमडी : ₹ 1,05,96,500/-. ई-बोली बंद होने की तिथि : 21.05.2022 को 11.00 बजे. ई-बोली खुलने की तिथि : 26.05.2022 को 15.00 बजे. निविदाकर्ताओं हेतु अनुदेश : 1) केवल ई-निविदा पोर्टल के जरिये ऑनलाइन जमा किये गये ई-प्रस्तावों पर ही विचार किया जायेगा. कृपया ध्यान दें कि प्रिंटेड प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा. 2) निविदा की तिथि, नियम एवं शर्तें तथा कार्य के विस्तार हमारी वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध हैं. 0814

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादक: लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोन: 079-22921482 Mob.9375504122, 9327086467 R.N.I. 63177/95